घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 12- बुधवार 12- नवम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये ,www.ghatati-ghatana.com,RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

दिल्ली ब्लास्टः गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी

मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है,फरीदाबाद से अरेस्ट डॉ. शाहीन जैश महिला विंग की हेड

पुलवामा से डॉ. उमर का दोस्त डॉ.सज्जाद गिरफ्तार मां और भाइयों के बाद अब पिता भी हिरासत में...

नई दिल्ली,11 नवम्बर 2025। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुआ था। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 घायलों का इलाज चल रहा है। दो शवों की पहचान हो गई है। बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। ब्लास्ट में जिस सफेद आई 20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक, कार में बैठे शख्स का नाम डॉ. मोहम्मद उमर नबी था। वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उसके डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और दो भाई को हिरासत में लिया है। पुलवामा से उसके दोस्त डॉ. सज्जाद और पिता को भी हिरासत में लिया गया है।

षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा : पीएम मोदी

सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत की और मेरी प्रतिबद्धता थी। लेकिन,आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। पीएम मोदी ने कहा, सोमवार शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि वे रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों और सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में थे। विचार-विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

दिल्ली विस्फोट के कारणों का जल्द पता लगाए सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट पर चिंता जताते हुए सरकार से इसके कारणों का जल्द पता लगाने की मांग की है। कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि इस धमाके के पीछे कौन लोग हैं और इसकी वजह क्या है, इसका पता जल्द लगाया जाना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि देश में चिंता और भय का माहौल है। देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने चाहिए। यह धमाका किसने कराया और इसके पीछे क्या सच्चाई है, जब तक सरकार इस पर जानकारी नहीं देती, तब तक इस मुद्दे पर बोलना वाजिब नहीं होगा।

दिल्ली में धमाका करने वालों को पकड़े जाने पर दी जाए फांसी : धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के आचार्य और कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की घटना पर प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के पलवल में पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जब भी धमाके हुए, उसे कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया। हमेशा भारत को,भारत माता को,सनातन को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वह घोर निंदनीय और अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है कि जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें वे अपने चरणों में स्थान दें। हम उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने अपील की कि कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो। ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे।

दिल्ली विस्फोट के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विस्फोट के बाद देश को दृढ़ता से आश्वस्त किया कि इस दुखद घटना के जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए नागरिकों को आश्वस्त किया कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक

कहा...दिल्ली धमाके के दोषियों को नहीं बख्शेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने दो अलग-अलग बैठकें कर अधिकारियों को अहम दिशानिर्देश दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शाह ने मंगलवार सुबह एक बैठक की अध्यक्षता की। दोपहर में भी एक बैठक बुलाई गई। सूत्रों ने बताया कि पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते भी शामिल हुए। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री के सामने विस्फोट के बाद उपजे हालात पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। सूत्रों ने बताया कि दोपहर की सुरक्षा समीक्षा बैठक में भी लगभग वही अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने विस्फोट की गंभीरता और हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एनआईए को जांच सौंपा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने इस वारदात को आतंकवादी कृत्य माना है। एनआईए को केवल आतंकवादी मामलों की जांच करने का अधिकार है।

कैसे चैनल झूठी खबरें चला सकते हैं जो हो रहा है,वह माफी के लायक नहीं : हेमा

नई दिल्ली,11 नवम्बर 2025। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच उनके परिवार और अभिनेता सनी देओल की टीम की ओर से जानकारी सामने आई है। धर्मेंद्र के परिवार ने अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वह डॉक्टरों की देखरेख में हैं। सनी की टीम ने कहा कि वे रिकवर हो रहे हैं। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। टीम ने बताया कि वह लगातार मीडिया से संपर्क में हैं और धर्मेंद्र की तबीयत पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर रोक लगाने की अपील की है। बता दें धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर झूठी खबरें सोशल मीडिया पर रातों-रात फैल गई थीं। कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना पुष्टि के दावा कर दिया था कि अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। इन खबरों को देखकर कई नामी हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि संदेश भी साझा कर दिए, लेकिन कुछ ही घंटों में धर्मेंद्र के परिवार ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि अभिनेता का इलाज चल रहा है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर इन झूठी खबरों की निंदा की। उन्होंने लिखा...जो हो रहा है,वह माफ करने लायक नहीं है। कैसे जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो अभी इलाज करा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं? यह गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक है। कृपया परिवार की निजता का सम्मान करें।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री के साथ किया ऐतिहासिक एमओयू साइन

नई दिल्ली,11 नवम्बर 2025। भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान अल सऊद ने रियाद में सांस्कृतिक सहयोग पर एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। शेखावत ने कहा कि यह एमओयू दोनों देशों के बीच कला, संगीत, साहित्य, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सांस्कृतिक संस्थानों के बीच संवाद बढ़ाने,सांस्कृतिक उत्सवों और आयोजनों में भागीदारी को आसान बनाने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हस्ताक्षर समारोह से पहले हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के संस्कृति मंत्रियों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में संयुक्त सहयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। यह एमओयू न केवल हमारी साझी विरासत को सशक्त करेगा, बल्कि भविष्य की सांस्कृतिक साझेदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

जेल से रिहा हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय,तीन साल बाद लौटे घर

कोलकाता,11 नवम्बर 2025। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को सोमवार को अदालत से मिली जमानत के बाद मंगलवार दोपहर को रिहा कर दिया गया। तीन साल, तीन महीने और 19 दिन जेल में रहने के बाद वे आखिरकार अपने नाकतला स्थित घर लौटे। दोपहर करीब 2:20 बजे वे बाइपास के पास स्थित अस्पताल से व्हीलचेयर पर बाहर निकले। जैसे ही वे अस्पताल के मुख्य द्वार पर आए, पहले से मौजूद समर्थकों ने 'पार्थ दा जिंदाबाद' के नारे लगाए। इस दृश्य को देखकर भावुक हुए पार्थ चट्टोपाध्याय की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केवल सिर हिलाकर उन्होंने संकेत दिया कि वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में रिकॉर्ड मतदान,शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग

पटना,11 नवम्बर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मंगलवार शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह पिछले दोनों चरण की तुलना में अधिक रहा, जिससे अंतिम चरण में मतदान को लेकर जबरदस्त रुझान देखा गया। सुबह से ही मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कई बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं। महिलाओं और युवा मतदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा। चुनाव आयोग के अनुसार, देर शाम तक के आंकड़ों में और वृद्धि की संभावना है, क्योंकि बूथों पर 6 बजे तक मतदान होना है। दूसरे चरण में कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ-साथ जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा था। अंतिम चरण के इस मतदान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब सभी की निगाहें मतगणना दिवस 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब जनता के जनादेश का फैसला सामने आएगा।

महागठबंधन जीतेगा : अशोक गहलोत

बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 'इस चुनाव में बिहार में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। उन्होंने (एनडीए) हर महिला को 10,000 रुपये बांटे। हमें उम्मीद है कि महिलाएं निष्पक्ष मतदान करेंगी। हमने कभी नहीं सुना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि महागठबंधन जीतेगा।'

मतदान के दौरान हिरासत में 13 लोग, कानून व्यवस्था में खलल का आरोप

शिवहर में मतदान के दौरान विधि व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में अलग-अलग स्थानों से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा तरियानी में शराब पीकर हंगामा करने के मामले में तरियानी प्रखंड प्रमुख प्रीति सिंह के पति राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

16 एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार

154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत,महागठबंधन को 84 सीटें,पीके की जन सुराज बेअसर

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी बढ़त के संकेत मिले हैं। 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 84 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। राज्य में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी फेज में रिकॉर्ड 67% मतदान हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनावों (2010, 2015, 2020) के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाईं। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीएयानी भाजपा+ को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं, 2020 में तस्वीर उलटी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणामों में एनडीएने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई।

युद्धाभ्यास 'अखंड प्रहार' के दौरान भारत ने रेगिस्तानी रणक्षेत्र में परखी सेना की ताकत

जोधपुर,11 नवम्बर 2025। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने रेगिस्तानी रणक्षेत्र में चल रहे अखंड प्रहार के तहत कोणार्क कोर की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। यह अभ्यास त्रिशूल ट्राइ-सर्विसेज एक्सरसाइज का अहम अध्याय है। इसने थल और वायु सेना की संयुक्त युद्ध क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ले. जनरल धीरज सेठ के अनुसार थार के कठिन इलाकों में अभ्यास ने मल्टी-डोमेन बैटलस्पेस में भारतीय सेना की शक्ति, समन्वय और तकनीकी उत्कृष्टता को नए स्तर पर दिखाया है। कम्बाइंड आर्म्स मैन्युवर्स के दौरान थलसेना और वायुसेना के बीच अपूर्व तालमेल दिखा। अभ्यास में कई नए टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसिजर्स को रियल-टाइम परिस्थितियों में परखा गया। इससे भविष्य के युद्ध अभियानों की रणनीतियों को और धार मिलेगी। ले. जनरल सेठ ने बैटल एक्स डिविजन और कोणार्क कोर के इनोवेशन का जायजा लिया। उन्होंने स्वदेशी ड्रोन, काउंटर-ड्रोन उपकरण और फोर्स प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे स्वनिर्मित रक्षा संसाधन देखे। ये संसाधन अब भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सेठ ने बैटल एक्स डिविजन की तकनीकी नवाचार, आत्मनिर्भर दृष्टिकोण और उच्च ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना तेजी से स्वदेशी तकनीकी संसाधनों की दिशा में आगे बढ़ रही है। अखंड प्रहार के दौरान हाई-टेक ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम्स की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ने भविष्य की हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीतियों को परखने का मौका दिया।

धमाके से दहला पाकिस्तान...इस्लामाबाद कोर्ट के पास हुआ आत्मघाती हमला,12 लोगों की मौत,36 घायल

शहबाज शरीफ का आरोप...भारत ने इस्लामाबाद में धमाके करवाए

इस्लामाबाद,11 नवम्बर 2025। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने मंगलवार को हुए इस्लामाबाद कोर्ट में हुए सुसाइड अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि यह हमला और अफगान सीमा के पास कैडेट कॉलेज पर हुआ हमला दोनों ही इंडिया स्पांसर्ड आतंकवादी घटनाएं हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर 1 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 36 घायल हुए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर तक सुनी गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम और सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की। पीएम शहबाज ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय आतंकियों के हमलों की मैंने कड़ी निंदा की है। मैंने घटना की तुरंत जांच करने का आदेश दिया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीएम शहबाज ने आगे कहा- हम बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे। हम आतंकवाद को मिटाने तक संघर्ष जारी रखेंगे। शहबाज ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया भारत की इन साजिशों की निंदा करे। भारत का यह चेहरा अब पूरे दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी जियो न्यूज के मुताबिक, यह विस्फोट एक सुसाइड अटैक था। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला है, जिससे आत्मघाती हमले की पुष्टि हुई है। इस हमले को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि देश अब 'जंग की स्थिति' में है। उन्होंने इस हमले के लिए अफगान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आसिफ ने कहा कि यह हमला दिखाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ सीमा इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ यह पूरा पाकिस्तान का युद्ध है और सेना अपने बलिदानों से देश को सुरक्षा का एहसास करा रही है।

दिल्ली में पांचवीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में होंगे संचालित : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली,11 नवम्बर 2025। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों की पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई अस्थायी रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार पांचवी कक्षा तक के छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगी ताकि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और कई अन्य प्रभावी निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अब मिशन मोड में और बिना किसी देरी के किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वायु प्रदूषण के तीन प्रमुख कारणों जैसे वाहन प्रदूषण, बायोमास बर्निंग या खुले में कूड़ा जलाना और धूल प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की गई।

संपादकीय

बैंकों से बेहतर है सहकारी नेटवर्क

बेहतर बदलाव की पहल

बढ़ई,कुम्हार,सुनार और दर्जी आदि 18 पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक नई उम्मीद लेकर आई थी। इसके तहत इन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और बिना जमानत के छोटा ऋण देने का प्रविधान है, ताकि वे आज की तकनीकी दुनिया में फिर से खड़े हो सकें। सितंबर 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण जीवन से संबंधित पारंपरिक पेशे थे।

दो साल बाद कागज पर तो आंकड़े उत्साहजनक दिखते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं, पर सच्चाई कुछ और है। अब तक सिर्फ 4.65 लाख कारीगरों को 4,000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 2,200 करोड़ रुपये ही वास्तव में वितरित हुए और मात्र 224 करोड़ रुपये की वापसी हुई है। पंजीकरण और वास्तविक कर्ज वितरण के बीच यह फासला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक कमी दर्शाता है। यह बताता है कि भारत में आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा रोड़ा बैंकिंग व्यवस्था ही है। निजी बैंक सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बस नियमों का चतुराई से पालन कर रहे हैं। आरबीआइ ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे अपनी कुल ऋण पुस्तिका का 40 प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र के साथ कमजोर वर्गों को दें। निजी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य को पूरा करने के बजाय प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र खरीद लेते हैं। ये प्रमाण-पत्र वे उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से खरीद सकते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित किया हो। कुछ बैंक अपने दायित्व को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से पूरा करने का दावा करते हैं। कागज पर वे नियम पूरा करते हैं, लेकिन हकीकत में विश्वकर्मा ऋण देने के मामले में निजी बैंकों का रिकार्ड निराशाजनक है। पीएम जन धन योजना में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी मुश्किल से तीन प्रतिशत है। निजी बैंकों का तर्क है कि दो लाख रुपये का एक छोटे कारीगर को दिया गया ऋण उतने ही कागजी काम और लागत मांगता है, जितना 20 लाख का कार लोन, पर मुनाफा बहुत कम।कारीगरों के पास न जमानत होती है, न डिजिटल ऋण इतिहास,जिससे जोखिम बढ़ जाता है। सरकारी गारंटी भी केवल आंशिक नुकसान कवर करती है। ऐसे में शेयरधारकों से संचालित संस्थानों के लिए यह काम आकर्षक नहीं है। इसके उलट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग पूरा बोझ उठाते हैं-चाहे जन धन,मुद्रा या विश्वकर्मा जैसी योजनाएं हों,लेकिन सीमित स्टाफ और सख्त नियामक बोझ के कारण उनकी क्षमता सीमित है। जब कर्ज अटकता है तो जनता के सामने दोष बैंक या सरकार,दोनों को झेलना पड़ता है।

मोहन भागवत का दावा और इतिहास के पन्ने

-राकेश प्रताप सिंह परिहार-

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का हालिया बयान,जिसमें उन्होंने दावा किया कि संघ ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया, उसे सम्मान दिया और उसकी रक्षा की, संगठन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करता है। भागवत का यह बयान बेंगलुरु में 100 इयर्स ऑफ संघ जनी न्यू होराइज़न्स नामक व्याख्यान श्रृंखला के दौरान आया,लेकिन यह विरोधाभासों और अस्पष्ट ऐतिहासिक तथ्यों से भरा हुआ प्रतीत होता है।

तिरंगे का विरोध, भगवा का आग्रह

भागवत का दावा है कि संघ ने सदैव तिरंगे का सम्मान किया, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण इसके विपरीत हैं। आजादी के ठीक पहले, आरएसएस के मुखपत्र *ऑर्गनाइज़र* में प्रकाशित संपादकीय (जुलाई-अगस्त 1947) स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे की निंदा करते थे। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गनाइज़र में लिखा गया कि जो लोग भाग्य के झटके से सत्ता में आए हैं, वे हमारे हाथों में तिरंगा दे सकते हैं, लेकिन इसे कभी हिंदुओं द्वारा सम्मानित और स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीन शब्द अपने आप में एक बुराई है, और तीन रंगों वाला ध्वज निश्चित रूप से एक बहुत ही खराब मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगा और देश के लिए हानिकारक है। यह सिर्फ़ एक संपादकीय विचार नहीं था। 1929-30 में जब कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने और तिरंगा फहराने का आह्वान किया, तब भी आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने अपनी सभी शाखाओं को भगवा ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज मानने का निर्देश दिया था, न कि तिरंगे को। यह विरोध वर्षों तक ऋस्स के मुख्यालय पर तिरंगा न फहराए जाने की प्रथा में भी परिलक्षित होता रहा सरकारी दबाव या स्वेच्छा से स्वीकृति तिरंगे के प्रति संघ की स्वीकार्यता स्वेच्छा से देशभक्ति की भावना से

आई, या यह सरकारी दबाव का परिणाम थी? ऐतिहासिक तथ्य बाद वाले की ओर इशारा करते हैं।महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को तभी हटाया गया जब आरएसएस ने लिखित रूप में संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति वफ़ादारी* का वादा किया। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की स्वीकार्यता एक कानूनी शर्त थी,न कि स्वाभाविक वैचारिक बदलाव। यहाँ तक कि 2001 में भी, नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वाले तीन युवा सदस्यों को जेल जाना पड़ा था, जिन्हें बाद में 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में बाइज्जत बरी किया गया। यह घटना भी संघ प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध तिरंगे को फहराने की एक मिसाल है।

संविधान और हिंदू महासभा का गठजोड़

मोहन भागवत का दावा केवल तिरंगे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संघ की विचारधारा में समय के साथ बदलाव की व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

संविधान का विरोध:- संविधान पारित होने के बाद दिल्ली के राम लीला मैदान में डॉ. भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने और संविधान की प्रतियाँ जलाने की घटनाएँ (जैसा कि आपके इनपुट में उल्लेख है) इस बात का प्रमाण हैं कि आरएसएस ने स्वेच्छा से संविधान को भी आसानी से नहीं स्वीकारा।

हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठजोड़

1940 के दशक की शुरुआत में हिंदू महासभा (जिसे कई आलोचक ऋस्स की वैचारिक जड़ मानते हैं) ने सिंध, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकारें बनाईं। यह तब हुआ जब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सत्ता से बाहर थी। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उपमुख्यमंत्री बनना और सिंध में पाकिस्तान प्रस्ताव के बावजूद मंत्रियों का बने रहना, संस्था के हिंदू रक्षक के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करने के दावे पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह दर्शाता है कि अवसरवाद की राजनीति उस समय भी एक प्रमुख कारक थी।

इतिहास को बदला नहीं जा सकता

मोहन भागवत का यह दावा कि संघ ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया *ऐतिहासिक रूप से गलत* है। यह बयान संघ के अतीत के उन विवादास्पद अध्यायों को मिटाने का प्रयास प्रतीत होता है, जिनमें तिरंगे के लिए अनादर, संविधान के प्रति विरोध और सत्ता की राजनीति में अवसरवादिता स्पष्ट रूप से दर्ज है।

कोई भी संस्था अपने इतिहास को बाद के बयानों से फिर से नहीं लिख सकती। आरएसएस ने अपनी स्थापना के शुरुआती दशकों में जो रुख अपनाया, उसे सरकारी दबाव और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण ही बदलना पड़ा। इतिहास को केवल %दबाव में स्वीकार्यता% के रूप में देखना ही उचित होगा, न कि हमेशा सम्मान के रूप में, जैसा कि भागवत ने दावा किया है।

करुणा एवं संवेदनाओं से ही दुनिया में संतुलन संभव

आज का मनुष्य जितनी तीव्रता से भौतिक प्रगति कर रहा है,उतनी ही तेजी से मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। विज्ञान ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, परंतु उसने मनुष्य को आत्मकेंद्रित भी कर दिया है। प्रतिस्पर्धा, उपभोगवाद, स्वार्थ और सत्ता की भूख ने मनुष्य के भीतर की दयालुता को जैसे कुंद कर दिया है।

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

ऐसे समय में जब विश्व हिंसा,आतंक,युद्ध,आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य के दौर से गुजर रहा है, तब विश्व दयालुता दिवस मनाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सभ्यता के विकास की असली पहचान तकनीकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की करुणा, सहानुभूति और प्रेम से होती है। दयालुता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाती है। इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने दया, करुणा और प्रेम को अपनाया, वहीं शांति और समृद्धि का आधार बने। बुद्ध, महावीर, यीशु और गांधी जैसे महापुरुषों ने दया को जीवन की सबसे बे ी साधना माना। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं, यह सबसे सक्रिय और जीवंत शक्ति है। दयालुता उसी अहिंसा की आत्मा है,जो मनुष्य को दूसरों के सुख-दुःख से जो ती है।

आज जब दुनिया में युद्ध की विभीषिका मंडरा रही है, जब समाज हिंसा,कट्टरता और असहिष्णुता से आक्रांत है, तब दया और करुणा का महत्त्व केवल नैतिकता का विषय नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। यूक्रेन-रूस युद्ध, गाजा और इस्राइल का संघर्ष,आतंकवाद की विभीषिका और भीतर तक उतर चुकी नफरत की राजनीति-ये सब इस बात के संकेत हैं कि हमने दयालुता को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। मनुष्य ने मशीनों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। संवेदना की जगह संदेह ने ले ली है, और करुणा की जगह क्रूरता ने। ऐसे में विश्व दयालुता दिवस केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं,बल्कि आत्ममंथन का अवसर है कि क्या हम अब भी मनुष्य बचे हैं या केवल उपभोग की दौ में शामिल यांत्रिक प्राणी बन गए हैं।

विश्व दयालुता दिवस मनाने की पहल सबसे पहले 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने की थी, जिसका उद्देश्य था-मानवता में करुणा, सहानुभूति और प्रेम के बीजों को फिर से सींचना। इस दिन का मकसद यह स्मरण कराना है कि दया कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि जीवन का स्थायी संस्कार होना चाहिए। दयालुता एक ऐसी भाषा है जो सभी सीमाओं, धर्मों, भाषाओं और विचारधाराओं से परे है। यह वह सूत्र है जो मनुष्यता को जो ता है, जो टूटे हुए रिश्तों में प्राण फूंकता है। आज की दुनिया में भौतिक विकास ने व्यक्ति को आराम तो दिया है, लेकिन आत्मिक शांति छीन ली है। हर कोई सफलता की हो में है, पर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। परिवारों में संवाद घट गया है, समाज में सहयोग की भावना कम हुई है, और राजनीति में विरोध ने वैमनस्य का रूप ले लिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में हम जु ते तो बहुत हैं, पर वास्तव में अलग-थलग पे गए हैं। दया और करुणा की कमी के कारण मानसिक तनाव, अवसाद, आत्महत्या और असंतोष जैसी समस्याएँ बे रही हैं। इस स्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय है-दयालुता की भावना को जीवन का आधार बनाना। दयालुता केवल दूसरों के प्रति व्यवहार नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के दुःख को समझते हैं, किसी की भूल को माफ करते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। दयालु व्यक्ति न केवल समाज को सुंदर बनाता है, बल्कि स्वयं के भीतर भी शांति का अनुभव करता है। करुणा से मनुष्य का हृदय विस्तृत होता है, दृष्टि उदार होती है, और जीवन में संतुलन आता है। आज की जटिल दुनिया में संतुलन खोना बहुत आसान है। मनुष्य अपनी इच्छाओं,आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं में उलझकर आत्मविनाश की ओर बे रहा है। पर्यावरण का संकट, सामाजिक विषमता, नैतिक पतन-ये सब उसी असंतुलन के परिणाम हैं, जहाँ दयालुता और करुणा का स्थान स्वार्थ और लोभ ने ले लिया है। यदि मनुष्य में करुणा का भाव जाग जाए, तो न युद्ध रहेगा, न आतंकवाद, न हिंसा। दुनिया में जितनी भी क्रूरताएं हुई हैं, वे दया के अभाव से हुई हैं। अतः दया केवल नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि है। युद्ध और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। दया और करुणा से ही समाज टिकता है, सभ्यता बचती है,और मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान पाता है। विश्व दयालुता दिवस इसलिए हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारे जीवन में दयालुता का स्थान बचा है? क्या हम अपने व्यवहार में दूसरों के सुख-दुःख के प्रति संवेदनशील हैं? दयालुता की शुरुआत बहुत छोटे-छोटे कार्यों से होती है-किसी की सहायता करना, किसी के प्रति मधुर बोल कहना, किसी की गलती को क्षमा करना, या किसी जरूरतमंद की मदद करना। इन छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं। यही छोटे कदम मिलकर समाज में बड़ी करुणा की लहर

विश्व शांति का आधार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था-÷जब तक एक भी जीव भूखा या दुखी है, तब तक तुम्हारी उपासना अधूरी है।÷ यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा या प्रार्थना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा का भाव है। यदि दयालुता जीवन का हिस्सा बन जाए, तो धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। चाहे वह जैन धर्म का ÷अहिंसा परमो धर्मः÷ का संदेश हो या बौद्ध धर्म की ÷मैत्री भावना÷, सभी ने दया को ही मानवता की सर्वोच्च साधना माना है। वास्तव में दया का अर्थ केवल किसी पर कृपा करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझना है। दया एक ऐसी ऊर्जा है जो न केवल संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज में सह-अस्तित्व की भावना को भी जन्म देती है। आज जब मनुष्य अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो दया ही वह सूत्र है जो जीवन में संतुलन और अर्थ दोनों ला सकती है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में तकनीकी शक्ति बढ़ रही है, परंतु नैतिक और भावनात्मक शक्ति घट रही पैदा करते हैं। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक दयालु कर्म हजारों हृदयों में प्रकाश फैला सकता है। आज जब दुनिया को हथियारों से नहीं, दिलों से जीतने की जरूरत है, तब दयालुता को जीवन का आधार बनाना सबसे बड़ी-बड़ी मानव सेवा है। करुणा वह सेतु है जो टूटे हुए संबंधों को जो ती है, घृणा को प्रेम में बदलती है और संघर्ष को सहयोग में परिवर्तित करती है। यही संतुलित, शांत और सुंदर जीवन की दिशा है। इसलिए विश्व दयालुता दिवस कोरा आयोजनात्मक न होकर प्रयोजनात्मक होना चाहिए, यह दिवस एक प्रेरणा है कि हम फिर से मनुष्य बनें, अपने भीतर की करुणा को जगाएं और दुनिया को प्रेम व सहानुभूति से भर दें। जब हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं, तो हम न केवल समाज में शांति फैलाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी दिव्यता का अनुभव करते हैं। यही दया का वास्तविक चमत्कार है-जो जीवन को संतुलित बनाता है और दुनिया को फिर से मानव बनाता है।

बच्चों के ग़लत फ़ैसले और परिवार की गिरती प्रतिष्ठा

डॉ.मुश्ताक़ अहमद शाह सहज
. हरदा,मध्य प्रदेश

आजकल के बच्चों में एक खेदजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है जहाँ वे अपनी निर्णय क्षमता को इतना बढ़ा लेते हैं कि वह अपने माता-पिता की इज्ज़त और खानदान की आबरू को नज़र अंदाज़ कर देते हैं। यह केवल उनकी व्यक्तिगत कमज़ोरी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के लिए एक बड़ा संकट भी है। मां-बाप की इज्ज़त और परिवार की सामाजिक गरिमा ही उस संस्कृति की नींव होती है जिसने हमें संवारा है। जब बच्चे अपने फ़ैसलों को अपनी स्वतंत्रता के नाम पर परिवार की इज्जत से ऊपर तोलते हैं, तो वह अपने पूरे खानदान की सामाजिक प्रतिष्ठा को गिरा देते

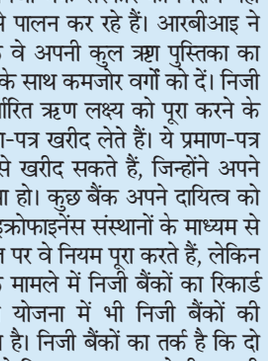

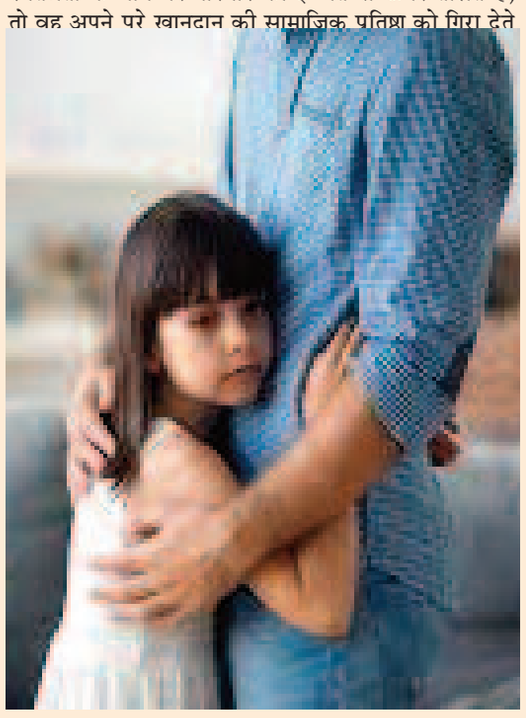

हैं। यह व्यवस्था मज़बूत रखने के लिए ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी में परिवार और समाज के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे, क्योंकि उनका भविष्य उन्हीं संस्कारों और परवरिशों के साथ जुड़ा होता है जिन्हें मां-बाप ने दिया होता है। जब बच्चे गंदगी और ऐसे फ़ैसलों को अपना भविष्य समझते हैं जो परिवार की इज्ज़त को नुकसान पहुंचाते हैं, तब यह पूरे खानदान के लिए अपमान का कारण बनता है। ऐसे निर्णय न केवल व्यक्तिगत जीवन को तोड़ते हैं,बल्कि सामाजिक रिश्तों और ख़ानदानी इज्जत को भी कमजोर करते हैं। यह अहंकार और समझ की कमी के कारण होता है जब बच्चे सोचते हैं कि डिग्री, पद या आधुनिकता उन्हें परिवार की इज्ज़त से ऊपर उठाती है, जबकि असली ताक़त उनके संस्कारों और विनम्रता में होती है,न कि इन बाहरी आभूषणों में। इस समस्या का समाधान संवाद, प्रेम और संस्कारों के पुनः प्रवर्तन में है, जिससे युवा पीढ़ी को अपने माता-पिता और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान की समझ हो। संस्कार, परिवार की गरिमा और सामाजिक आचार विचार के प्रति सम्मान के बिना कोई भी डिग्री या पद असली सफलता नहीं दे सकता। आज की परिस्थिति में जब युवा अपनी ग़लत राहों को सही समझते हुए अपने खानदान की इज्जत गिरा रहे हैं, वहां ज़रूरत है कि फ़रि से परिवारों में संवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि ये बच्चे समझ सकें कि असली औकात परवरिश और तहज़ीब में है, न कि केवल दिखावे या उच्च पदों में। इसलिए आज के समाज को चाहिए कि वे अपनी नई पीढ़ी को केवल विद्या नहीं बल्कि सम्मान और संवेदना की भी शिक्षा दें ताकि वे अपने फ़ैसलों में परिवार की इज्ज़त और समाज की मर्यादा को हमेशा प्राथमिकता दें।

ज्ञान के वृहद् स्वरुप राष्ट्र का वैश्विक स्वरुप

राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा,ज्ञान की भूमिका

यह सर्वविदित है कि इतिहास का पन्ना पलटें तो हर सभ्यता ने अपने कई कई रूप बदले हैं। संस्कृति ने नए नए नए आयाम का सृजन किया हैद्य वैसे भी जीवन परिवर्तन का पर्याय है एवं विकास का स्वरूप है। यह सर्वकालीन सत्य है कि शिक्षा एवं ज्ञान का महत्व हर संस्कृति, सभ्यता और मानवीय समुदाय के जीवन में एक प्रकाश पुंज की तरह उन्हें विकास की दिशा दिखाते हुए आया है। जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होगी उस देश की सभ्यता संस्कृति और ज्ञान उत्तम शिखर पर होगा और विकास की नई नई धाराएं बहेगी। मानवीय विकास के साथ मनुष्य को अधिक परिपक्व को समझदार तथा समृद्ध बनाने में शिक्षा,भाषा,ज्ञान और साहित्य का सर्वाधिक महत्व रहा है। शिक्षा चाहे आपके परिवार से प्राप्त हुई हो, स्कूल कॉलेज अथवा किसी शिक्षण संस्थान से प्राप्त हुई हो या भारतीय संस्कृति के वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हुई हो, शिक्षा का मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी अहम भूमिका होती हैद्य शिक्षा भी समाज संस्कृति एवं सभ्यताओं के साथ परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील है। शिक्षा, ज्ञान तथा संस्कृति और कला साहित्य को देश और विदेश की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। यह असीमित भंडार है एवं इसमें आकाशीय ऊंचाइयां भी शामिल रहती हैं। शिक्षा और ज्ञान न तो गहराइयां न ही नापी नजा सकती है, और ना ही इसकी ऊंचाई को देखा जा सकता है। पूर्वी सभ्यता जहां अध्यात्म, वेद ,पुराणों पर अवलंबित है, वहीं पश्चिमी सभ्यता ज्ञान विज्ञान नए नए अविष्कार और आकाश की अनछुई कई बातों को उजागर करने वाली है। ऐसी शिक्षा तथा ज्ञान के कारण मानव चंद्रमा पर पहुंच कर एक नई गाथा लिख पाया है। वस्तुतः पूर्व तथा पश्चिम ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षा के मामले में एकाकार हो चुका है कोई भी भेदभाव या विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है। पूरी सभ्यता ने जहां पाश्चात्य दर्शन से नए नए अविष्कारों हवाई जहाज, इंजन, ग्रामोफोन, रेडियो एवं नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है वहीं पश्चिमी दर्शन ने भारती ज्ञान विज्ञान संस्कार आयुर्वेद योग धर्म दर्शन को अपना कर अपनी जीवनशैली में शांति तथा सौभाग्य स्थापित किया है। यह सब शिक्षा भाषा एवं ज्ञान के बदौलत पूर्व और पश्चिम का मेल संभव हो पाया है। शिक्षा और भाषा सदैव ही अज्ञानता के तमस में एक प्रकाश पुंज की तरह देदीप्यमान होता रहा है, नवजीवन की विकास धारा में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया हैद्य हमारे कई धर्मों में जिनमें जैन ,बौद्ध दर्शन, नव्य वेदांत तथा भारतीय संस्कृति के नवीन चिंतन के सामने आने से नवयुग की कल्पना को साकार किया है। पश्चिम के कई विद्वान और चिंतक जिनमें प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, कार्ल मार्क्स, लेनिन ने अनेक विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जिसका पूरे विश्व ने खुले दिल से स्वागत किया एवं विकास की नई नई की इबारत लिखी है। दूसरी ओर भारत की संस्कृति, सभ्यता और समाज में सदैव आवश्यक सुधार तथा नई नई बुद्धिमता पूर्ण युक्तियों को अपने में आत्मसात करने की एक अलग क्षमता रही है, और विकास का मूल मंत्र भी परिवर्तनशील जीवनशैली ही है द्य राजनीति तो सदैव परिवर्तन पर अवलंबित रहती है। स्वतंत्रता के पहले तथा बाद में राजनीतिक घटनाक्रम जिस नव परिवर्तन युग की तरफ अग्रसर हुए हैं वह अत्यंत उल्लेखनीय हैद्य भारतीय सभ्यता समाज और संस्कृति जितनी जटिल तथा गूढ है उसको जितना समझा जाए, उसका जितना अध्ययन किया जाए तो उससे नवीन बातें समझ में आती है, और उसके नए नए अर्थ हमारे सामने आते हैं, जिसका बहु आयामी उपयोग हम अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करने के लिए सदैव कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद तो भारत देश ने ज्ञान भाषा तथा संस्कृति में अनेक परिवर्तन किए गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अपनी किताबों में नव परिवर्तन के नए-नए आयामों तथा जीवन शैली के सत्य के साथ प्रयोग को एक नया आयाम दिया है और भारत देश को नए स्वरूप में विश्व में पहचान दिलाई है। पाश्चात्य ज्ञान से हमें अपने आडंबर एवं अंधविश्वास तथा शिक्षा पर विजय प्राप्त करने में काफी मदद प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति की कई भ्रांतियों को भी हमने ज्ञान तथा भाषा के नवीन प्रयोगो से समाज से दूर किया है। दिन प्रतिदिन जीवन की कार्यशैली में हम यह महसूस करते हैं कि शिक्षा भाषा तथा ज्ञान हमें यह महसूस कर आते हैं कि हम अभी तक कितने पीछे हैं एवं हमें कितने ज्ञान की और आवश्यकता है।

संजीव ठाकुर,
रायपुर,छत्तीसगढ़,

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

न्यायालय को 10 किलोमीटर दूर ले जाने की जिद....

आखिर किसका हित? किस पर दबाव?

अधिवक्ता अनिश्चितकालीन आंदोलन पर...जिला प्रशासन और न्याय विभाग अब भी मौन...

ऐसी क्या मजबूरी है कि जमीन होते हुए भी न्याय विभाग व जिला प्रशासन शहर से 10 किलोमीटर दूर न्यायालय बनाना चाहता है?

अधिवक्ता का कहना है कि मध्य शहर में न्यायालय में गोली बंदूक चलती है तो फिर 10 किलोमीटर दूर क्या स्थिति उत्पन्न होगी यह कौन विचार करेगा?

क्या न्यायालय सिर्फ न्यायालय विभाग और जिला प्रशासन की सुविधा के लिए है, या फिर अधिवक्ता और आम जनता भी न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं?

जब शहर के बीचो-बीच न्यायालय बनाने का तय हो गया था फिर अचानक प्रशासन क्यों पलटी मार?

क्या प्रशासन व न्याय विभाग दोनों एकमत होकर अधिवक्ताओं व वहां पर आने वाले पक्षकारों की समस्या बढ़ाना चाहते हैं?

फिर अंबिकापुर में सरकार बनाम सरकार!
न्यायालय वही बने जहाँ जनता के लिए न्याय प्राप्त करना सरल हो,न्याय जनता के बीच रहे...जनता से दूर नहीं : सम्पूर्णाक

न्यायालय भवन स्थानांतरण पर विवाद तेज
जिला अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी
प्रशासन पर दादागिरी, दबाव और भ्रामक प्रचार के आरोप
न्यायालय भवन स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश
अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी...प्रशासन पर दबाव व भ्रामक प्रचार के आरोप

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर 11 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

न्यायालय भवन सिर्फ एक ढांचा नहीं होता,यह न्याय उपलब्धता का केंद्र होता है,यहां न्यायाधीश और कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब अधिवक्ता अपनी दलीलें रखते हैं और पक्षकार अपनी बातें कह पाते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न्याय की पूरी संरचना अधिवक्ता,पक्षकार और जनता से मिलकर चलती है, तो न्यायालय के निर्माण या स्थान चयन जैसे निर्णय में इन्हीं लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? यदि न्यायालय को जनता की पहुँच से दूर ले जाया जाता है, तो इसका सीधा मतलब है न्याय पाने में दूरी बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, और अंततः न्याय तक पहुंच कठिन होगी,तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है: क्या न्यायालय की इमारत बनाने वाले लोग न्याय की आत्मा को समझते भी हैं? या फिर यह पूरा निर्णय सिर्फ दफ्तरों के एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर कलम चलाने जैसा है? न्यायालय जनता के लिए होता है। यदि जनता और उसके प्रतिनिधि (अधिवक्ता) ही संघर्षरत हों, आंदोलन पर हों, तो यह संकेत है कि निर्णय न्यायहित में नहीं, बल्कि किसी और हित में लिया गया है।

बता दे की सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में जिला न्यायालय को शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर प्रस्तावित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है, अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि यह निर्णय व्यावहारिक नहीं,जनविरोधी है और गरीब, ग्रामीण,महिला एवं दिव्यांग पक्षकारों के लिए न्याय तक पहुंच को और कठिन बना देगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर न तो जिला प्रशासन कोई ठोस कारण बता पा रहा है और न ही न्याय विभाग द्वारा अब तक कोई सार्वजनिक पक्ष रखा गया है। सांसद चिंतामणि महाराज,विधायक राजेश अग्रवाल,लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, अंबिकापुर महापौर और विपक्ष के नेता टी.एस. सिंहदेव सभी ने वकीलों की मांग को जायज बताया है तो फिर दिक्कत कहाँ है? अब असली प्रश्न क्या डिस्ट्रिक्ट जज का भूमि माँगने वाला पत्र वैध है?

जमीन उपलब्ध होने के बावजूद न्यायालय को 10 किलोमीटर दूर ले पर गंभीर सवाल, क्या यह 'कब्जाधारियों' को बचाने का खेल है?-

अधिवक्ता संघ के सचिव सम्पूर्णांक गुप्ता के अनुसार, जब तत्कालीन माननीय चीफ जस्टिस महोदय अंबिकापुर आए थे, उस समय डब्ल्यूडी द्वारा 2 एकड़ 69 डिसमिल भूमि को न्यायालय निर्माण के लिए विधिवत मापा गया था, इसी भूमि पर न्यायालय भवन के लिए पूरा नक्शा (डिज़ाइन) स्वीकृत हुआ, और लगभग 46 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर हो गया था। यह लगभग ढाई वर्ष पहले की आधिकारिक प्रक्रिया है जिसे किसी ने न तो चुनौती दी, न विरोध, इसके उपरांत, अधिवक्ता संघ के अनुरोध पर और न्यायालय की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर द्वारा गुलाब कॉलोनी क्षेत्र को न्यायालय परिसर में शामिल कर दिया गया, इसके बाद न्यायालय के लिए उपलब्ध भूमि बढ़कर 4 एकड़ से अधिक हो गई, अर्थात न्यायालय निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी, स्वीकृत थी, और बजट तक जारी था, इसी क्रम में, अप्रैल में सरगुजा कमिश्नर द्वारा गुलाब कॉलोनी में निवासरत कर्मचारियों को 'बेदखली नोटिस' भी जारी किया गया था, ताकि जमीन को निर्माण के लिए खाली कराया जा सके, लेकिन आज की स्थिति यह है गुलाब कॉलोनी में शासकीय राजस्व कर्मचारी, सिविल कोर्ट से जुड़े कर्मचारी, यहां तक कि कोर्ट प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी खुद कब्जाधारी के रूप में निवास किए हुए हैं। जिनमें कोर्ट मैनेजर युवराज सिंह और न्यायालय अधीक्षक जैसे नाम भी शामिल हैं, यानी न्यायालय की जमीन पर सबसे पहले कब्जा किसका? जिन्हें न्याय व्यवस्था चलती है उन्हीं का, और यही सबसे बड़ा प्रश्न है।

तो क्या कब्जा हटाने की जगह न्यायालय को ही शहर से बाहर भेजने की साजिश हो रही है?

जब कब्जाधारी सरकारी कर्मचारी जमीन खाली नहीं कर रहे, तो जमीन को वापस लेने की बजाय, न्यायालय को ही 10 किलोमीटर दूर ले जाने का प्रस्ताव क्यों? यह स्थिति सीधे-सीधे संकेत करती है कि: कब्जाधारियों को बचाने के लिए निर्माण स्थल बदला जा रहा है जनता और अधिवक्ताओं की सुविधा का ध्यान जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है यह प्रशासनिक क्षमता का सवाल नहीं इच्छाशक्ति और दबाव का प्रश्न है।

पहले जहां बनाने का निर्णय हुआ था,वही जमीन क्यों खाली नहीं करवाई जा रही?

यह तथ्य स्वयं प्रशासनिक अभिलेखों में दर्ज है कि: दो वर्ष पूर्व गुलाब कॉलोनी को न्यायालय परिसर में शामिल कर दिया गया था, यहां कुल 4 एकड़ से अधिक भूमि न्यायालय निर्माण हेतु उपलब्ध है,भूमि मापन और नक्शा (डिज़ाइन) बन चुका है, 46 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत एवं आवंटित हो चुका है, अप्रैल माह में कर्मचारियों को बेदखली नोटिस भी जारी किया गया था, तो फिर सवाल है, जिस जमीन पर न्यायालय बनना था,वह आज तक खाली क्यों नहीं करवाई गई? क्या कुछ प्रभावशाली कब्जाधारियों को बचाने के लिए न्यायालय को शहर से बाहर धकेला जा रहा है? क्या सरकारी आवासों पर कब्जा किए बैठे कुछ व्यक्तियों के हितों के सामने पूरी न्याय व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है? यह सवाल सिर्फ अधिवक्ताओं का नहीं, बल्कि न्याय चाहने वाली जनता का है।

सुरक्षा का गंभीर सवाल, शहर में गोली चल सकती है तो 10 किमी दूर क्या होगा?

अधिवक्ता संघ के सचिव सम्पूर्णांक गुप्ता ने कहा: 'जब शहर के बीच में स्थित न्यायालय परिसर में भी पहले गोली-कांड हो चुका है, तो फिर 10 किलोमीटर दूर सुनसान क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।' यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरगुजा संभाग का यह सबसे बड़ा न्यायालय है यहां रोजाना हजारों लोग आते हैं, पुलिस बल की उपलब्धता पहले से सीमित है, क्या दूरस्थ स्थान पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना तैयार हुई है? यदि नहीं, तो यह निर्णय किस आधार पर लिया जा रहा है?

वकीलों और प्रबुद्ध नागरिकों के 10 किलोमीटर दूर न्यायालय बनने से ये होगी परेशानी

न्यायालय शहर से दूर चले जाने पर एसडीएम, कलेक्टर,तहसील कार्यालय सब डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे,जिससे वकीलों और पक्षकारों की दौड़-धूप बढ़ेगी, अंबिकापुर संभाग मुख्यालय है यहाँ ग्रामीण लोग एसपी, आईजी या कलेक्टर को आवेदन देने आते हैं। आवेदन तैयार करने के लिए वकील जरूरी होते हैं। न्यायालय दूर हुआ तो लोगों को अलग-अलग स्थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वर्तमान में टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाम्प वेन्डर आदि एक ही परिसर में हैं, यह सुविधा खत्म हो जाएगी। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय एक स्थान पर हैं,इसलिए वकील एक ही दिन में कई मामलों की पैरवी कर पाते हैं, कोर्ट दूर हुआ तो न्याय देर से मिलेगी, वरिष्ठ वकीलों की उपस्थिति से प्रशासनिक अधिकारियों पर नैतिक दबाव रहता है,जिससे रिश्वतखोरी पर कुछ हद तक अंकुश रहता है,अगर न्यायालय दूर होगा, तो यह नियंत्रण घटेगा और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। वकीलों की प्रमुख मांग है कि- सभी न्यायालय (राजस्व , सेशन, उपभोक्ता फोरम, तहसील आदि) एक ही स्थान पर रहें, वर्तमान परिसर के पास (पूर्व में कलाकेंद्र मैदान या पश्चिम दिशा में रिंग रोड पार) भी पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, मल्टी-स्टोरी भवन, अंडरग्राउंड पार्किंग और आधुनिक सुविधाओं के साथ नया न्यायालय बनाया जा सकता है, यदि सरकार शहर से बाहर ही ले जाना चाहती है तो फिर छठिरमा क्षेत्र में कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दफ्तर और आवास भी साथ बनाए जा सकते हैं ताकि समन्वय बना रहे।

जनता की सुविधा की अनदेखी, न्याय तक पहुंच को कठिन बनाना क्या न्याय है?

यदि न्यायालय शहर से बाहर चला जाता है, तो: ग्रामीण और गरीब पक्षकारों का किराया बढ़ेगा,दूर दराज के क्षेत्रों से आने वालों के लिए ऑटो,बस,वाहन उपलब्धता की समस्या बढ़ेगी, महिला,बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच और अधिक कठिन हो जाएगी, अधिवक्ताओं पर दैनिक आर्थिक और समयगत बोझ बढ़ेगा,क्या न्याय व्यवस्था सिर्फ विभागीय कर्मचारियों के लिए है? या न्याय पाने वाले आम लोगों के लिए भी?

जनता और अधिवक्ता,दोनों को नजरअंदाज, आखिर किसके इशारे पर फैसला?

अधिवक्ताओं ने बार-बार अनुरोध किया: बैठक बुलाओ, तर्क सुनो विकल्प देखो, परंतु प्रशासन चुप, न्याय विभाग चुप,नेतृत्व चुप,क्या यह चुप्पी किसी बड़े दबाव की ओर संकेत करती है? यदि नहीं, तो फिर खुलकर तथ्य क्यों नहीं रखे जा रहे? जनता और अधिवक्ताओं की एक ही मांग- न्यायालय शहर में ही बने, जहां पहले से जमीन उपलब्ध है, वहां कब्जे हटाकर निर्माण शुरू किया जाए, न्याय की पहुंच को दूर करना न्याय से समझौता है।

सबसे सीधा सवाल प्रशासन और न्याय विभाग से जब न्यायालय निर्माण की जमीन उपलब्ध, स्वीकृत, नक्शा पास, बजट जारी और बेदखली आदेश लागू है,

- तो फिर शहर से 10 किलोमीटर दूर न्यायालय क्यों?
- अचानक ऐसा क्या हुआ?
- किसके दबाव में निर्णय बदला गया?
- किस हित के लिए अधिवक्ताओं और जनता को कठिनाइयों में डाला जा रहा है?

अंतिम सवाल, और यह सवाल जनता का है...

- न्यायालय किसके लिए है?
- न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए?
- क्या न्यायालय विभाग अकेला न्याय का स्वामी है?
- क्या जिला प्रशासन यह मान चुका है कि निर्णय केवल ऊपर की मेजों पर होते हैं, जनता सिर्फ उसे झेलती है?
- क्या अधिवक्ता सिर्फ औपचारिकता हैं, जिनकी राय की कोई कीमत नहीं?
- और सबसे महत्वपूर्ण – न्याय मांगने वाले आम नागरिक का मूल्य क्या है इस पूरी प्रक्रिया में?

डॉ. हेडगेवार के जीवन पर अद्भुत नाट्य मंचन देख भावविभोर हुए दर्शक

डॉ हेडगेवार ने राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया : लक्ष्मी राजवाड़े

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित नाट्य मंचन का आयोजन स्थानीय पी.जी. कॉलेज के सभागार में छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग एवं संस्कार सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य व संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता तथा आरएसएस प्रांत सेवा प्रमुख तुलसी दास व संस्कार सेवा समिति अध्यक्ष भगवान दास बंसल के विशिष्ट आतिथ्य में नादब्रम्हा नाट्य ग्रुप द्वारा आयोजित

नाट्य मंचन की अद्भुत प्रस्तुतियों से सभागार में उपस्थित दर्शक भावविभोर हो उठे। नाट्य प्रस्तुति के दौरान डॉ हेडगेवार जी के प्रत्येक संवाद पर 'वंदे मातरम' व 'भारत माता की जय' के जयकारों से पूरा सभागार गुंजायमान हो उठा। अंबिकापुर शहर में लंबे समय बाद नाट्य विधा का जीवंत अभिनय पूर्ण चित्रण कला प्रेमियों को देखने को मिला जिसकी सबने भूरि भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि डॉ हेडगेवार ने राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने कहा कि एकता, अनुशासन व राष्ट्रीय चेतना से ही भारत देश आगे बढ़ेगा यही डॉ हेडगेवार जी की सोंच थी। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि परम पूज्य डॉ हेडगेवार जी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा हेतु समर्पित था। डॉ हेडगेवार कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। इस अवसर पर नादब्रम्ह नाट्य ग्रुप के निर्माता पद्माकर धानोरकर ने बताया कि महाराष्ट्र व गोवा के बाद तीसरा छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां उनकी नाट्य प्रस्तुति को दर्शकों का अद्भुत प्रतिसाद व प्यार मिल रहा है, आगे देश के अन्य राज्यों में भी उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी।

3 महीने से लापाता किशोरी की लाश कंकाल के रूप में मिली,नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

तीन महीने से लापाता किशोरी की लाश कंकाल के रूप में बतौली थाना क्षेत्र के चिरगा जंगल में मिली। नाबालिग प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव को पहाड़ के खाई में डाल दिया था। शव कंकाल के रूप में मिला। पुलिस ने मौके से किशोरी के कपड़े व कंकाल बरामद किए। प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इंजानी निवासी 17 वर्षीय किशोरी अंबिकापुर के पटपरिया इलाके में किराए के मकान में सहेली के साथ रहकर काम करती थी। उसका परिचय लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ससौली निवासी नाबालिग लड़के से हुआ था। किशोर से उसकी मोबाइल पर बातचीत होती थी तथा उसके किराए के रूम में आना-जाना था। 3 अगस्त को किशोरी की सहेली अपने गांव गई थी। इसी बीच किशोर उससे मिलने आया। यहां किशोरी ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया। इस पर उसने कहा कि अभी हम दोनों नाबालिग हैं। बात किसी तरह से खत्म होने के बाद किशोर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाने ले गया। दोनों बतौली थाना क्षेत्र के बुढ़ाआमा

पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे थे। यहां से लौटने के दौरान किशोर ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। नाबालिग प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने उसका शव वहीं दो चट्टानों के बीच फेंककर दफन कर दिया था। इसके बाद वह अपने गांव लौट गया था। इधर 4 अगस्त को परिजनों को किशोरी के गायब होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने उसकी खोजबीन शुरु की। उसके नहीं मिलने पर उन्होंने 10 सितंबर को गांधीनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस मामले की जांच प्रेम प्रसंग के एंगल से भी कर रही थी। किशोरी का मोबाइल बंद बता रहा था। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस पर लगा रखा था।

CMYK

कस्टोडियल डेथ पर बवाल : हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत के बाद उठे सवाल,चार दिन से शव के अंतिम संस्कार पर ठहराव

परिजन बोले...पुलिस की पिटाई से हुई मौत...निष्पक्ष पोस्टमार्टम और कार्रवाई तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार

- परिजनों का आरोप पुलिस ने पीट-पीट कर मार डाला,रात्रि में ही आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने डाला दबाव
- हिरासत में लेने के बाद परिजनों से मिलने नहीं दिया,मृत्यु उपरांत गोपनीय तरीके से कराया पोस्टमार्टम
- सर्व आदिवासी समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने हेतु दिया गया आवेदन
- मृतक की मां ने प्रदेश के राज्यपाल को भी अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से दिया आवेदन,की कार्यवाही की मांग
- क्षेत्र की यह पहली घटना नहीं,जहां पुलिस हिरासत में हुई हो मृत्यु

-न्यूज डेस्क-

बलरामपुर/सरगुजा,11 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में एक बार फिर पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। बलरामपुर थाना क्षेत्र में चोरी के कथित आरोपी युवक उमेश सिंह (19 वर्ष),निवासी ग्राम नकना की 9 नवंबर को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई,मामला तूल तब पकड़ गया जब परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि पुलिस की मारपीट से हुई है, मृतक के परिजनों ने चार दिन से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है और निष्पक्ष जांच व दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़े हुए हैं, परिजन और ग्रामवासी बलरामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद रातों-रात पुलिस ने शव को गांव भेजकर अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाया और मुआवजा व नगद देने की पेशकश भी की गई। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल हैंडलिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं की थर्ड डिग्री का प्रयोग न हो,आवश्यक होने पर ही हिरासत दी जाए, गिरफ्तारी के बाद परिजनों से मिलने से नहीं रोका जाए फिर भी प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं। वैसे यह मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि विश्वास बनाम अविश्वास का है, एक ओर पुलिस बीमारी से मौत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर परिजन और समाज कस्टोडियल टॉर्चर की बात कह रहे हैं, अब पूरा मामला निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग की पुलिसिया कार्यप्रणाली की पहचान अब कस्टोडियल डेथ से भी होने लगी है, एक के बाद एक होने वाले कस्टोडियल डेथ के कारण सवाल उठना लाजमी है, ताजा घटना बलरामपुर जिले की है,जहां बलरामपुर थाने में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, हालांकि पुलिस वालों के अनुसार युवक बीमार था और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, बावजूद इसके सैकड़ों सवाल मुंह बाए खड़े हैं, जब युवक बीमार था और बहुत कमजोर था तो उसे हिरासत में लिया ही क्यों गया? क्यों उसे समय अनुसार अस्पताल में दाखिल नहीं कराया गया? उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे पाए गए? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब हिरासत में लिया गया तो युवक के साथ मारपीट क्यों की गई? आनन फानन में पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? चुपचाप अंतिम संस्कार के लिए परिजनों पर दबाव क्यों डाला गया? परिजनों को मुआवजा राशि देने एवं पुलिस वालों द्वारा नगद पैसे देने का प्रलोभन क्यों दिया गया? ऐसे अनेकों सवाल हैं, जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कस्टोडियल डेथ का यह संभाग में पहला मामला नहीं है, विगत कुछ वर्षों में और भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मृतक के परिजन आज तक न्याय के गुहार लगा रहे हैं,सरकारें बदल गई, परंतु परिस्थितियों जस की तस है,यह मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां परिजन युवक की मृत्यु को पुलिस द्वारा किया गया हत्या बता रहे हैं, विडंबना यह है की मृत्यु के चार दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक युवक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है, और उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और निष्पक्ष पोस्टमार्टम नहीं होता वह शव स्वीकार नहीं करेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे।

आम आदमी पार्टी ने न्याय के लिए आईजी कार्यालय के सामने दिया धरना

घटनाक्रम में मृत युवक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय नेता भी सामने आए और आईजी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए आम आदमी पार्टी ने निष्पक्ष जांच न होने की दशा में आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

परिजनों का आरोप

सादे लिबास में ले जाकर पीटा, मिलने नहीं दिया गया- मृतक की मां ने पुलिसकर्मियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है,और प्रदेश के राज्यपाल को सीतापुर के अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मृतक युवक की मां के अनुसार 7 नवंबर 2025 शाम लगभग 5:00 बलरामपुर थाने के पुलिसकर्मी जो की सादे लिबास में थे, उन्होंने युवक उमेश सिंह पिता फेकू सिंह उम्र 19 वर्ष को सीतापुर के ग्राम नकना के वार्ड क्रमांक 1 से हिरासत में लिया और प्रत्यक्ष दर्शियों की उपस्थिति में युवक के साथ मारपीट करते हुए अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर चले गए, मृतक की मां को एक दिन बाद सीतापुर थाने से बुलावा आया, जहां से वाहन द्वारा इन्हें बलरामपुर थाने भेजा गया। बलरामपुर थाने में युवक के परिजन युवक से मिलने का गुहार लगाते रहे, परंतु इन्हें युवक से मिलने नहीं दिया गया। 9 नवंबर 2025 की रात्रि में इन्हें सूचना दी गई की युवक की मृत्यु हो गई है, और थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा आनन-फानन में युवक के शव को एंबुलेंस में रखकर ग्राम नकना के लिए यह कहकर रवाना किया गया कि इसका अंतिम संस्कार कर दो,सरकार द्वारा मुआवजा मिलेगा और कुछ पैसा हम भी तुम्हें देंगे,मृतक युवक की मां का यह भी आरोप है कि रात भर थाना और पुलिस के चक्कर काटने के बाद सुबह युवक के शव के साथ रवाना किया गया। पोस्टमार्टम के लिए मृतक के परिजनों की सहमति भी नहीं ली गई और पुलिस कर्मियों को युवक के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी ? अपनी शिकायत में पांच सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम और उचित जांच उपरांत दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।

सरगुजा समाचार | अम्बिकापुर, मंगलवार 11 नवम्बर 2025 | 3

पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बलरामपुर में तनाव

पुलिस हिरासत में क्यों हो रही मौत? छत्तीसगढ़ पुलिस की बर्बरता क्यों नहीं खत्म हो रही?

- बलरामपुर जिले में पुलिस अधीक्षक में दूसरी मौत व संभाग में तीसरी मौत
- परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप,शव लेने से किया इनकार ...प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच का दिया आदेश...
- पुलिस अभिरक्षा में मौत के बढ़ते मामले सवालों के घेरे में...
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी नहीं थम रही कस्टडी डेथ की घटनाएँ

सर्व आदिवासी समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने हेतु दिया गया आवेदन

सर्व आदिवासी समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के लिए आज आवेदन सौंपा गया। सर्व आदिवासी समाज की मांग है कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष जांच हो, शव का पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए,कस्टोडियल डेथ होने की दशा में मृतक के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा मिले और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अपने आवेदन में सर्व आदिवासी समाज ने जो कुछ वर्णित किया है, उसके अनुसार पूरा का पूरा मामला संदिग्ध नजर आता है। आवेदन में दिए गए तथ्यों के अनुसार युवक की मृत्यु हो जाने के उपरांत परिजनों को सीतापुर से बुलाया गया, जिसकी व्यवस्था भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने ही की। युवक से मिलने के लिए टालमटोल लगातार किया गया, परिजनों को कहा गया कि युवक अस्पताल में भर्ती है। वहां भी परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता, अचानक परिजनों को सूचना दी जाती है कि युवक की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद भी जब परिजन मृत्यु युवक के शव को देखना चाहते हैं, तो उन्हें दूत्कारा जाता है। और यह कहा जाता है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और चिरफाड चल रही है, इसके बाद आपको शव सौंप दिया जाएगा। उसके बाद का घटनाक्रम तो और भी विचित्र है, जहां मृत युवक की लाश को सौंपने के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए तत्काल में दबाव डाला जाता है, रुपए, पैसे और मुआवजा का प्रलोभन दिया जाता है। इन सबसे क्षुब्ध होकर परिजनों द्वारा युवक के शव को लेने से इनकार कर दिया गया। जिसकी परिणति यह है कि चार दिन बीत जाने पर भी अभी तक युवक का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है।

प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री संभाग के ही और संभाग के आदिवासी सुरक्षित नहीं...

छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व स्वास्थ मंत्री अमरजीत भगत ने पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली और सरकार पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री मिला,तो प्रदेश के आदिवासियों के मन में यह आशा जगी कि चलो अब हम सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। परंतु जब प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री अपने ही संभाग के आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो पूरे प्रदेश के साथ क्या न्याय करेंगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि घटनाक्रम का जो वर्णन हमारे सामने आया है उसके अनुसार जब युवक हिरासत में ले जाते वक्त ठीक था, तो दो दिन बाद उसकी मृत्यु पुलिस हिरासत में कैसे हो गई? परिजनों को युवक से मिलने क्यों नहीं दिया गया और परिजनों को भी क्यों प्रताड़ित किया गया ? यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के जिला प्रशासन और सरगुजा संभाग के आईजी से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी का आरोप...

चाहे कस्टोडियल डेथ का मामला हो या आरोपियों को सरेआम,सरे बाजार हथकड़ी लगाकर जुलूस निकालने का,इसके अतिरिक्त और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निश्चित है,हिरासत में किसी की मृत्यु ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है कि थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए,अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यदि कोई आरोपी है भी, तो उसके भी मानवाधिकार होते हैं,यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो सामान्य परिस्थितियों में उसे हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। आरोप सिद्ध होने के पूर्व हथकड़ी के साथ जुलूस निकालना कहां तक न्याय संगत होता है,परंतु छत्तीसगढ़ पुलिस ने शायद यह ठान लिया है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं करना है। जिसकी परिणति कस्टोडियल डेथ के रूप में यहां सामने आई है। और भी पूरे प्रदेश में ताजा मामले हुए हैं जहां पर किसी मामले में गिरफ्तार आरोपी को सरे आम हथकड़ी लगाकर उसका जुलूस निकाला गया है। जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत है।

मामला अब किस मोड़ पर...

- शव अस्पताल में संरक्षित है
- परिजन निष्पक्ष जांच तक अंतिम संस्कार से इंकार
- संगठन और सामाजिक समूह मामले पर सक्रिय
- प्रशासन जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कह रहा है

अनूपपुर में प्रशासन के साथ पत्रकारों की ऐतिहासिक बैठक : निष्पक्ष पत्रकारिता को मिला नया संबल

कलेक्टर एवं एसपी ने दिया भरोसा 'पत्रकारों की सभी समस्याओं का होगा निष्पक्ष समाधान'

- पत्रकार एकता मंच ने जताया आभार,कहा...यह शुरुआत है...अंत नहीं
- आंदोलन स्थगित कर पत्रकारों ने दिखाया संवाद की शक्ति
- अनूपपुर में पत्रकार आंदोलन का असर-प्रशासन आया संवाद की राह पर

-संवाददाता-

अनूपपुर,11 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पत्रकार एकता मंच अनूपपुर के बैनर तले पत्रकारों की एकता और संघर्ष ने आखिरकार प्रशासन को संवाद के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार को जिला मुख्यालय के नर्मदा सभागार में कलेक्टर हर्षल पंचोली और पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के साथ पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक को जिले की पत्रकारिता के इतिहास में 'जनसरोकार की जीत' और 'संवाद से समाधान की दिशा' के रूप में देखा जा रहा है।

पत्रकारों की एकता बनी बदलाव की ताकत : 8 नवंबर को अनूपपुर जिले के पत्रकारों ने न्यू बस स्टैंड स्थित आंदोलन स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया था। इस आंदोलन की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम कमलेश पुरी, एडिशनल एसपी मरकाम,एवं कोतवाली थाना प्रभारी को मौके पर भेजा था। उनकी मध्यस्थता के बाद प्रशासन ने संवाद के लिए बैठक का दिन तय किया, जिसके बाद पत्रकारों ने जनहित और सौहार्द को प्राथमिकता देते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया।

पत्रकारों ने रखी अपनी बात-झूठे प्रकरणों पर कार्रवाई की मांग : बैठक में पत्रकारों ने वन-टू-वन चर्चा के दौरान अपनी पीड़ा, उत्पीड़न और कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को खुलकर सामने रखा। उन्होंने कहा...'सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता करना अब चुनौती बन चुका है। स्वतंत्र पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, धमकियां और नोटिस भेजकर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर जल्द निराकरण हो। ' पत्रकारों ने यह भी मांग रखी कि – फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कवरेज के दौरान पुलिस द्वारा उत्पीड़न या प्रतिबंध की घटनाओं पर सख्त रोक लगे। स्वतंत्र पत्रकारों को सरकारी कार्यक्रमों में समान अवसर मिले।

कलेक्टर और एसपी का भरोसा-'पत्रकार लोकतंत्र की ताकत हैं : बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने स्पष्ट कहा... 'पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ हैं। आप निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करें, प्रशासन आपके साथ है। ' वहीं एसपी मोती उर रहमान ने कहा...'पत्रकारों की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच होगी। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता का सम्मान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाएगी। ' दोनों अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि पत्रकारों से जुड़े सभी मामलों पर रिपोर्ट तलब की जा रही है और प्रत्येक प्रकरण पर निष्पक्ष निर्णय जल्द लिया जाएगा।

पत्रकार एकता मंच ने जताया आभार : पत्रकार एकता मंच अनूपपुर ने जिला प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा यह बैठक पत्रकारों की एकता और संवाद की जीत है। हम प्रशासन के सहयोग से जनहित में काम जारी रखेंगे।

संघर्ष से संवाद की राह : यह बैठक इस बात का प्रतीक बनी कि जब पत्रकार एक मंच पर एकजुट होते हैं, तो उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं किया जा सकता। पत्रकारों का संघर्ष केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि जनता की सच्चाई को निर्भीकता से सामने लाने के अधिकार के लिए है।

CMYK

क्या नगर पंचायत पटना के प्रथम सीएमओ की छुट्टी बना उनका 'ढाल'?

नगर पंचायत पटना : प्रथम सीएमओ के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला,छुट्टी पर भेजे जाने के बाद उठे सवाल

आर्थिक अनियमितता साबित होने उपरांत सीएमओ भेजे गए छुट्टी पर...क्या सीएमओ को बचाने छुट्टी को बनाया गया हथियार?

नवगठित नगर पंचायत पटना के प्रथम सीएमओ का भ्रष्टाचार जांच में भी हुआ साबित,कार्यवाही की जगह तबादले का मिलेगा इनामःसूत्र

नगर के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों की प्रमुख मांगें...

- भ्रष्टाचार पर स्पष्ट एवं स्वतंत्र जांच की कार्यवाही
- दोष सिद्ध होने पर विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई
- केवल स्थानांतरण नहीं,जवाबदेही तय हो

-रवि सिंह-

कोरिया/पटना,11 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

नवगठित नगर पंचायत पटना में प्रथम बार पदस्थ किए गए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों ने नगर के प्रशासनिक माहौल को गर्म कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतों और विभागीय जांच के बाद कई आर्थिक गड़बड़ियों की पुष्टि होने पर संबंधित सीएमओ को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसी निर्णय ने अब सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में शामिल होने का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना था, मगर आरोप हैं कि नगर पंचायत गठन के बाद से ही कई कार्यों में नियम प्रक्रिया और पारदर्शिता की अनदेखी की गई। शिकायतों के आधार पर हुई जांच रिपोर्ट में भी आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आई, जिसके बाद सीएमओ को छुट्टी पर भेजा गया।

बता दे की सुशासन छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान मानी जाती है वहीं सरकार लगातार सुशासन की बात भी करती है वहीं यदि सुशासन को लेकर जमीनी हकीकत देखी जाए तो सुशासन नजर आता नहीं है,वर्तमान मामला कोरिया जिले के नवगठित नगर पंचायत पटना का है जहां नगर गठन से लेकर अब तक प्रथम सीएमओ बनकर काम कर रहे अधिकारी द्वारा नगर को अपने लिए भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया गया है और कई मामलों में शिकायत और जांच उपरांत जब भ्रष्टाचार साबित भी हो चुका है तब सीएमओ को लंबी छुट्टी पर भेजकर उसे बचाए जाने का प्रयास हो रहा है,नवगठित नगर पंचायत पटना के लोगों ने ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में शामिल होने की सहमति इसलिए प्रदान की थी जिससे नगर के अनुसार ग्राम का विकास हो और नगर के लोगों को बेहतर सुविधा और बेहतर अवसर प्राप्त हो वहीं प्रथम सीएमओ ने अपने पदस्थ होने से लेकर अब तक जो कुछ नगर पंचायत में किया वह केवल अपनी जेब भरने का काम था जो साबित हुआ जब शिकायत पर जांच हुई,अब सीएमओ को लंबी छुट्टी दी गई है और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या छुट्टी प्रदान करने के पीछे का कारण सीएमओ को बचाना है?वैसे सीएमओ अपने तबादले के लिए प्रयासरत है और बताया जा रहा है कि ऐसा संभव भी हो सकता है क्योंकि सीएमओ पहुंच और जुगाड में माहिर है, अब यदि तबादला होता है तो यह माना जाएगा कि यह इनाम है सीएमओ के लिए उसके भ्रष्टाचार का,वैसे सूत्रों का मानना है कि सीएमओ का तबादला ही किया जायेगा कार्यवाही भ्रष्टाचार साबित होने उपरांत भी नहीं होगी यह खुद सीएमओ लोगों से कहते सुने जाते हैं, वैसे नव गठित नगर पंचायत पटना के नागरिक एवं प्रथम नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि सीएमओ पर कड़ी कार्यवाही चाहते थे लेकिन भ्रष्टाचार साबित होने उपरांत भी सीएमओ पर लंबे समय तक कार्यवाही नहीं होने से अब वह कार्यवाही से बच निकलेंगे यह तय नजर आ रहा है,वैसे फिलहाल

क्या पटना से हटाने के बाद मामले पर होगी कार्रवाई?

प्रशासनिक संकेतों के अनुसार, सीएमओ का स्थानांतरण संभावित माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानांतरण के बाद जांच स्वतः समाप्त मानी जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो यह जनमानस में गलत संदेश जाएगा कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में भी केवल कुर्सी बदली जाती है, जवाबदेही नहीं तय की जाती।

शासन के सुशासन मॉडल पर सवाल

राज्य सरकार स्वयं को सुशासन मॉडल पर कार्यरत बताती है, लेकिन यदि वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद भी कार्रवाई के बजाय प्रभावशाली नेटवर्क और जुगाड़ भारी पड़ जाता है तो यह व्यवस्था की गंभीर कमजोरी दर्शाता है, मामला अब जांच और निर्णय के बीच अटका है, यदि कार्रवाई होती है तो यह सुशासन की पुष्टि होगी, और यदि केवल स्थानांतरण होता है तो यह यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं, संरक्षण प्राप्त होता है।

नागरिकों की अपेक्षा

नवगठित नगर पंचायत पटना के स्थानीय नागरिकों का अब स्पष्ट मत है कि उन्हें ऐसा सीएमओ चाहिए जो नगर विकास को प्राथमिकता दे, न कि व्यक्तिगत दायरे को।

नवगठित नगर के नागरिकों को जनप्रतिनिधियों को वर्तमान सीएमओ की बजाए दूसरा सीएमओ चाहिए जो नगर विकास ज्यादा,स्व विकास कम करे।

क्या पटना से हटाने के बाद उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी?

नगर पंचायत पटना के सीएमओ को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है,अब इसके बाद कयास यही लगाया जा रहा है कि उन्हें हटाने की कवायद की यह शुरुआत है,वैसे माना जाता है कि शासकीय विभागों में किसी को किसी जगह से हटाए जाने के दौरान यदि उसे लंबी छुट्टी में भेजा गया है तो ऐसा उसे कड़ी कार्यवाहियों से बचाने के लिए किया गया है क्योंकि ऐसा कुछ गंभीर मामलों में जिसमें,वित्तीय अनियमितता,भ्रष्टाचार या गबन जैसे मामलों में ही होता है,सीएमओ को हटाया जाना तय माना जा रहा है और यदि उन्हें हटाया जा रहा है तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी भ्रष्टाचार मामले में यह सवाल खड़ा हो रहा है,सीएमओ की कारगुजारी वैसे क्षमा योग्य नहीं है फिर भी वह तबादले की कार्यवाही से बचने वाले हैं यह तय नजर आ रहा है।

सीएमओ के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही से बचाने दी गई लंबी छुट्टी

सीएमओ को लंबी छुट्टी पर भेजने के पीछे की मंशा उन्हें लंबी कार्यवाही से बचाना है,सीएमओ का भ्रष्टाचार ऐसा भ्रष्टाचार है जो साबित हो चुका है जिसकी जांच विभाग ने ही की है,सीएमओ जांच उपरांत कार्यवाही से नहीं बच सकते इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया है,वैसे जनता जनप्रतिनिधि कार्यवाही की मांग जरूर कर रहे हैं और जिसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है,सीएमओ लंबी छुट्टी के दौरान ही अन्य जगह पदस्थ कर दिए जाएंगे ऐसा वह दावा करते सुने जाते हैं।

क्या भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों को संरक्षण इस सरकार में भी मिलेगा?

सीएमओ को यदि केवल तबादला कर अन्य जगह भेज दिया जाता है और कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है,वैसे यदि ऐसा होता है,कार्यवाही नहीं होती है तो यह सवाल खड़ा जरूर होगा कि इस सरकार में भी क्या भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होगा।

क्या छुट्टी को बनाया गया 'ढाल'?

सूत्रों का दावा है कि सीएमओ को छुट्टी पर भेजे जाने के पीछे उन्हें विभागीय कार्रवाई या निलंबन से बचाना मुख्य कारण हो सकता है, इसके पीछे तर्क यह बताया जा रहा है कि छुट्टी दिए जाने के बाद कुछ समय बीतने पर सीएमओ का स्थानांतरण कर दिया जाएगा ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के मामलों की फाइल आगे नहीं बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि स्थानांतरण ही अंतिम परिणाम रहा, तो यह भ्रष्टाचार के बदले इनाम देने जैसा होगा।

सोनहत एसडीएम कार्यालय तक पहुँचने वाली सड़कें जर्जर, युथ कांग्रेस ने किया विरोध

फारेस्ट चौक, धुम्माडांड सहित मुख्य मार्गों पर गड्ढे ही गड्ढे, मरम्मत की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-

सोनहत,11 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

सोनहत में बुनियादी सड़क व्यवस्था की खराब हालत के खिलाफ युवा कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। युथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू और वीरेंद्र साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनहत को ज्ञापन सौंपकर तत्काल सड़क मरम्मत की मांग की, युवाओं ने कहा कि सोनहत फारेस्ट चौक से एसडीएम कार्यालय तक जाने वाली सड़क इस कदर जर्जर हो चुकी है कि रोजाना आने-जाने वाले लोगों को खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि गड्ढे कम और सड़क ज्यादा ढूंढनी पड़ती है।

धुम्माडांड और स्कूल के रास्ते की स्थिति बदत्तर

युवा कांग्रेस ने बताया कि...भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल से प्राथमिक शाला धुम्माडांड मार्ग सोनहत से केशगवांङ्गबेलिया संपर्क मार्ग इनकी हालत सबसे खराब है,इन्हीं रास्तों से रोज़ सैकड़ों बच्चे स्कूल आते-जाते हैं, और अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रही हैं।

मजार चौक से हाउसिंग बोर्ड तक की सड़क टूटी

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि- मजार चौक, जनपद पंचायत हटमेंट कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड, तहसील कार्यालय, कोलपारा मार्ग दोनों मार्गों में डामर और गिट्टी पूरी तरह उखड़ चुके हैं, सड़क जगह-जगह खड्डों में तब्दील हो चुकी है।

नवीन महाविद्यालय तक जाने वाला मार्ग भी परेशानी का कारण

भारत स्कूल से नवीन महाविद्यालय और हसदो नदी तट तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह खराब हो चुकी है। इसी मार्ग से छात्र,ग्रामीण,मरीजों सहित रोजमर्रा के लोग आते-जाते हैं, लेकिन मरम्मत के कोई संकेत नहीं दिख रहे।

युवाओं की मांग...

युवा कांग्रेस ने प्रशासन से स्पष्ट कहा यह समस्या अब असहनीय है, सड़कें तुरंत ठीक की जाए, वरना आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू सहित युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रशासन के द्वारा जप्त स्टोन क्रेशर की हुई चोरी

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,11 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत पैनारी में शिवानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुल बनाने का ठेका लिया है और इनके द्वारा छोटे झाड के जंगल की भूमि खसरा नंबर 1080 पर अवैध रूप से शासन प्रशासन के बिना अनुमति के स्टोन क्रेशर मशीन लगाया गया था जिसे खड़गवां के तात्कालिक तहसीलदार एवं खनिज विभाग एमसीबी के अधिकारियों के द्वारा हुई शिकायत पर स्टोन क्रेशर मशीन को जप्त किया गया था। जांच कर्ता अधिकारीयों ने जब क्रेशर संचालक से स्टोन क्रेशर मशीन के दस्तावेज मांगे गए तो किसी प्रकार के कोई स्टोन क्रेशर मशीन लगाने के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए गए ग्राम पंचायत खनिज विभाग राजस्व विभाग के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के धड़ल्ले से क्रेशर मशीन का निर्माण कार्य किया गया था

क्या चोरी के प्रकरण में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती हैं क्या मालिक को नोटिस भेजा जाता है...वह मामला कई सवालों को जन्म दे रहा है?

शासन और प्रशासन के सारे नियम कायदों का उलंघन करते हुए सारे नियमों को ताक में रखकर निर्माण किया गया था जिसे खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग ने क्रेशर मशीन को जप्त किया गया था। इस जप्त क्रेशर मशीन की कुछ सामाग्री कोड़ा पुलिस चौकी में रखी गई थी। प्रशासन के द्वारा जप्त स्टोन क्रेशर मशीन को उखाड़ कर चोरी कर ले गए और खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग सिर्फ नोटिस भेज कर हाथ पर हाथ रखकर बैठा है।

इस जप्त स्टोन क्रेशर मशीन पर हुए लाखों रूपए के जुर्माने को बिना जमा किए दबंगई से स्टोन क्रेशर मशीन को उखाड़ कर लें गये जबकि प्रशासन के द्वारा जप्त किया गया था जो प्रशासन के पास जप्त था?

जप्त क्रेशर मशीन को स्थल से चोरी हुए लगभग चार से पांच माह हो गए आज तक खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग सिर्फ जप्त क्रेशर मशीन के मालिक को नोटिस ही दे सका है जबकि जप्त स्टोन क्रेशर मशीन का जप्त स्थल से गायब होना या चोरी होने की रिपोर्ट करना चाहिए जप्त क्रेशर मशीन शासन की संपत्ति है जिसका चोरी होना विभाग पर कई सवाल खड़े कर रहा है? क्या खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग इस पर कार्यवाही करेगा?

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विद्युत कार्य हेतु निविदा सूचना

निविदा संख्या.: टीआरडी-बीएसपी-291-25-26, दिनांक: 04.11.2025.

कार्य: (1) बिलासपुर: बिलासपुर डिवीजन में सीआईसी सेक्शन पर भूमिगत केबल द्वारा 33 केवी ओवरहेड पावर लाइन क्रॉसिंग का संशोधन। (2) बिलासपुर डिवीजन में बैहाटोला–अंबिकापुर, बोरीडांड–चिरिमिरी और बिलासपुर यार्ड के बीच भूमिगत केबल द्वारा 33 केवी ओवर हेड पावर लाइन क्रॉसिंग का संशोधन। (3) बिलासपुर मंडल अंबिकापुर में वाशिंग पिट/कोचिंग मेंटेनेंस टर्मिनल का प्रावधान। **निविदा मूल्य:** ₹ 3,10,86,685.05. **अमानत राशि:** ₹ 3,05,400.00.

निविदा जमा करने की तिथि: 26.11.2025 के 15:00 बजे तक।

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी/ निविदा दस्तावेज का विक्रय, पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क.वि.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के कार्यालय में संपर्क करें अथवा निविदा कागजात जो हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है उससे डाउनलोड कर/देख सकते है।

वरि.मंडल विद्युत अभियंता(क.वि.)/ बिलासपुर
सीपीआर/10/445

South East Central Railway @secrai

R.O. No.MUM01552/25-26
R.O. Date 11-11-2025

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय मित्तल आ0सत्यनारायण मित्तल निवासी अग्रसेन चौक अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम भिटठीकला स्थित व्यपवर्तित भूमि खसरा नंबर 121/2, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5. 136 रकबा 0.202, 0.094, 0.093, 0.093, 0.093, 0.093, 0.210 हे0 कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 0.878 भूमि को अनावेदक श्वेता मित्तल पति रमेश कुमार मित्तल व अन्य निवासी अग्रसेन चौक अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 12.11.2025 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-14/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी अंबिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ-20(3)/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक बलदेव प्रसाद सोनी आ0 स्व0 साधु साव सोनी आयु लगभग 88 साल जाति सोनार निवासी पंचशील गली अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला देवीगंज रोड नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर 3 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1038/2 रकबा 0.04,1/2 एकड़ भूमि मे से रकबा 14.4 X 32.10= 462.24 वर्गफीट भूमि को रूपये-10,00,000-00 अनावेदक / क्रेता संजय श्रीवास्तव आ0 स्व0 राधिका रमण श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26/11/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 11//11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत कसनिया डिपों में होने वाले ई-नीलाम के लिये प्रस्तावित जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के विभिन्न डिपो में रखे गये वनोपज के नीलाम हेतु मात्रा की जानकारी

नीलाम दिनांक 18.11.2025

अ.क्र	डिपो का नाम	प्रजाति	पिछले नीलाम का शेष							योग						
			लट्ठा		बल्ली/डेंगरी		जलाउ	बांस		लट्ठा		बल्ली/डेंगरी		जलाउ	बांस	
			नग	घ.मी.	नग	घ.मी.	चठ्ठा	नग	नो.टन	नग	घ.मी	नग	घ.मी	चठ्ठा	नग	नो.टन
1	निस्तार डिपो सक्ती	अन्य	56	9.233						56	9.233	0	0.000			
		सागौन	30	2.880						30	2.880	0	0.000			
		साल	14	1.828						14	1.828	0	0.000			
		सतकठा					57			0	0	0	0.000	57		
2	अकलतरा डिपो	सागौन	29	3.846	384	3.127				29	3.846	384	3.127			
		नीलगिरी			1498	34.059				0	0	1498	34.059			
		सतकठा								0	0	0	0.000			
		अद्योबांस						70	0.044	0	0	0	0.000		70	0
3	जांजगीर	सागौन	16	0.943	4	0.046				16	0.943	4	0.046			
		अन्य	184	26.511						184	26.511	0	0.000			
		सतकठा					114			0	0.000	0	0.000	114		
4	पतोरा डिपो	तेन्दू	130	20.861						130	20.861	0	0.000			
		साजा	45	9.337						45	9.337	0	0.000			
		अन्य	30	4.174						30	4.174	0	0.000			
		हल्दू	6	1.059						6	1.059	0	0.000			
		बीजा	4	0.572						4	0.572	0	0.000			
		साल	39	6.045	6	0.027				39	6.045	6	0.027			
		सागोन			6	0.101				0		6	0.101			
		सतकठा					1			0			0.000	1		
योग			583	87.289	1898	37.360	172	70	0.044	583	87.289	1898	37.360	172	70	0.044

क्रेताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व MSTC E-Commerce Portal में रजिस्टेशन में करना अनिवार्य है ।
2 क्रेताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वालेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदारों को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत EMD की राशि जमा करना अनिवार्य है ।
3 लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो MSTC E-Commerce Portal में अपने आई.डी से लॉग इन करके देख सकते है
4 केताओं द्वारा 40 सेकण्ड पूर्व क्रय करने पर 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा ।

जी.नं.-252604635/2

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में

भ्रष्टाचार का काला तालाब ?

गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों का पर्याय बना राष्ट्रीय उद्यान

दीवार टूट गई और सच भी, भ्रष्टाचार पर तिरपाल डालकर वन विभाग समझ बैठा कि मामला दब जाएगा...

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के तालाब की दीवार पर भ्रष्टाचार की तिरपाल

सोनहत पार्क परिक्षेत्र में 2 साल पूर्व बनाया गया तालाब 2 माह पहले फूटा,आनन-फानन में दीवार को पुनः मरम्मत करा कर तिरपाल से ढांका गया

सोनहत पार्क परिक्षेत्र के कही फूटे तालाब तो कही भारी बारिश के बाद भी बेहद कम पानी,क्या गर्मी में सुख जाएंगे तालाब ?

क्या भ्रष्टाचार छुपाने तालाब की दीवार को प्लास्टिक से ढका गया ?

कई शिकायतों के बाद भी कार्यवाही नही, क्या बड़े अधिकारियों का भी है संरक्षण ?, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में कब खत्म होंगी अनियमितताएं ?

-राजन पाण्डेय-

कोरिया, 11 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

गुरुघासीदास दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में भ्रष्टाचार अब ढंका नहीं, खुला नंगा नाच बन चुका है,सोनहत पार्क परिक्षेत्र में दो वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से बनाया गया तालाब सिर्फ दो मौसम भी नहीं टिक सका और बारिश आते ही धड़ाम! तालाब की दीवार टूट गई,और फिर क्या किया गया?मरम्मत नहीं, भ्रष्टाचार की 'लाज' बचाने तिरपाल ओढ़ा दी गई! हाँ,तालाब को रेनकोट पहना दिया गया! ये वही तिरपाल है, जो अक्सर बरसाती में सब्जी वाला खरीदता है, उसी से सरकारी भ्रष्टाचार ढकने का प्रयास किया गया। यह भ्रष्टाचार की तिरपाल अब फटने वाली है और जब यह फटेगी चेहरे भी देखेंगे, नाम भी सामने आएंगे।बता दे की गुरुघासीदास दास राष्ट्रीय उद्यान में अनियमितताए खत्म होने का नाम ही नही ले रही हैं, एक के।बाद एक नए मामले उजागर होते जा रहे हैं बावजूद इसके अधिकारियों को कोई परवाह नही है, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी कर्मचारियों को विभाग के छवि धूमिल होने की भी परवाह नही है। कुछ दिवस पूर्व जनकपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का मामला उजागर हुआ था अभी ताज़ा मामला सोनहत परिक्षेत्र से आया है जहां तालाब निर्माण में भारी भर्राशाही की गई,और नतीजा यह हुआ कि तालाब फुट गया,हालांकि यह मामला लगभग 2 माह पुराना है लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसे अति गोपनीय रखा और तालाब के दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण विभाग के लोग आस्वस्त थे कि यहां कोई देखने नही आएगा,सूत्र बताते हैं कि जब तालाब फूटा तो प्रबंधन आनन फानन में मरम्मत में जुटा और जैसे तैसे मिट्टी पाट कर उसे मरम्मत किया गया,तालाब के निकासी पानी अर्थात ओवर फ्लो सिस्टम को इतना बढ़ा दिया गया कि अब कभी दुबारा उस बड़े तालाब में ज्यादा पानी स्टोर नही हो सकेगा।

जिले से लेकर मंत्री तक शिकायत और नतीजा ?

चुप्पी,मौन,गोद में हाथ रखकर बैठी हुई प्रशासनिक 'निर्मित' बेहोशी, चाहे...स्टाफ डेम घोटाला हो,तालाब निर्माण या सड़क जिससे बारिश में मिट्टी बह जाए, शिकायतें खरीदी जाती हैं,जांचें दफन की जाती हैं, फाइलें सुन्नों की कब्र में दबा दी जाती हैं।

सवाल सिर्फ एक, क्या टाइगर रिजर्व भ्रष्टाचारियों का रिजर्व है ?

जब तालाब तक नहीं बन पा रहे, तो पानी रखने की क्षमता क्या होगी? और फिर उसी पानी से टाइगर प्रोजेक्ट चलता है! टाइगर नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेगा,और कारण सिर्फ एक, भ्रष्टाचार जंगल को खा रहा है।

अब कार्रवाई नहीं,संघर्ष होगा...

कोरिया जन सहयोग समिति ने घोषणा कर दी है पार्क परिक्षेत्र का घेराव होगा,गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई,तो आंदोलन होगा, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा अब भरोसा प्रशासन पर नहीं अब जवाब सड़क पर मांगेंगे।

यह तिरपाल मिट्टी नहीं,चोरों की मिली जुली समझौता-पत्र है

विभाग डर में है,भय में है। गलती उजागर होने के डर से तालाब की दीवार पर काला पर्दा चढ़ा दिया गया, काला पर्दा दीवार पर नहीं, वन विभाग की ईमानदारी पर पड़ा है।

और देखिए खेल...

तालाब फूटा,फिर मरम्मत,फिर तिरपाल,और अब ओवरफ्लो चैनल इतना छोटा कर दिया गया कि तालाब में पानी भर ही न सके,यानी तालाब रहे भी,तो खाली रहे,ताकि अगली बार टूटने का खतरा ही नहीं, यह कोई इंजीनियरिंग नहीं, घोटाले को स्थायी सुरक्षा देने की तकनीक है।

बिना इंजीनियर करोड़ों के काम,और फिर पूछते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है!

यहाँ तालाब,बांध,सड़क,डेम –सब डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड के भरोसे, जिन्हें यह भी नहीं पता कि...दीवार ढलाई कितनी होनी चाहिए,पानी का दबाव कैसे सहा जाता है, सॉइल कंसोलिडेशन कैसे होता है। लेकिन टेंडर? कांट्रेक्टर? लाखों का भुगतान? सब सही! यानी ज्ञान ग़ायब,पैसा चालू।

पार्क परिक्षेत्र अधिकारी 'अंगद का पैर'

जिधर अधिकारी बैठा, उधर की कुर्सी 5-6 साल से हिली नहीं, यह पोस्टिंग है या जायदाद? किसके आशीर्वाद से? किस सौदे के बदले? यह जनता पूछ रही है...और जवाब अभी तक जंगल के सन्नाटे में खो गया है।

ऐसे प्रबंधन से सरकार की छवि हो रही खराबःजयचन्द

सोनहत क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता जयचंद सोनपाकार ने आरोप लगाते हुए कहा की की राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से गिटटी एवं रेत उत्खनन कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है। जो कि सीधे सीधे नियम विपरीत है कही तालाब टूट रहे हैं कही मिट्टी मुरुम सड़क बह जा रही है, बस कुछ नही हो रहा तो वह है जांच और कार्यवाही, जयचन्द ने कहा कि अब प्रशासन से जांच की उम्मीद नही बची है, ऐसे प्रबंधन के कारण शासन की छवि खराब हो रही है।

कोरिया जन सहयोग समिति करेगी पार्क का घेरावःपुष्पेंद्र

कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि पार्क परिक्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में पूर्व में कई गई शिकायतों पर जांच व कार्यवाही नही होने से क्षेत्र के लोगो मे भारी नाराजगी है, बहुत जल्द पार्क परिक्षेत्र कार्यालय का घेराव कर जांच एवं कार्यवाही की मांग किया जाएगा।

पार्क परिक्षेत्र में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच होःजनार्दन गुप्ता

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता जनार्दन गुप्ता ने कहा लंबे समय से हो रही शिकायतों पर जांच व कार्यवाही नहीं होना बेहद दुर्भाग्य जनक है, पार्क परिक्षेत्र के अनियमितताओं पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है

मनेंद्रगढ़ को मिली बड़ी सौगातः पाराडोल एनीकट निर्माण को मिली 10 करोड़ 4 लाख की स्वीकृति

स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार...

-संवाददाता-

एमसीबी, 11 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। हसदेव नदी पर पाराडोल एनीकट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग की तरफ से 10 करोड़ 4 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से मनेंद्रगढ़ के लगभग 80 हेक्टेयर क्षेत्र में निस्तारी,पेयजल,भूजल संवर्धन एवं कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है, वहीं मनेंद्रगढ़ की स्थानीय जनता ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विधायक तथा कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार जताया है,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद कहा है कि यह एनीकट सिंचाई, भूजल संवर्धन, पेयजल, निस्तारी कार्य और क्षेत्र के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगा और स्थानीय जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

CMYK

इन हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका

ये मोस्ट अवेटेड मूवी भी है शामिल

2025 और 2026 के बीच कई हॉरर कॉमेडी,साइकोलॉजिकल हॉरर और हॉरर फिल्में रिलीज होने वाली हैं,जो आपका मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वश लेवल 2, थम्मा और मलयालम फिल्म डाइस इरा जैसी कई फिल्में बड़े पर्दे पर पहले ही तहलका मचा चुकी हैं। ऐसे में अब कई नई रोमांचक इंडियन हॉरर फिल्में दस्तक देने वाली है। आने वाली फिल्मों की लाइनअप दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने का वादा करती है।

2025 और 2026 में आने वाली इंडियन हॉरर फिल्में-

1. झाड़ फूंक

रिलीज डेट - विंटर 2025

हिंदी हॉरर फिल्म झाड़ फूंक विंटर 2025 में रिलीज होने वाली है। राजन रामगोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी, यशपाल शर्मा, सुम्बुल तौकीर, हर्ष राजपूत, अप्रतिम सिंह और दूसरे कलाकार अहम रोल में हैं। कहानी और सही रिलीज डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि, मेकर्स ने फिल्म का टीजर 24 अगस्त, 2025 को रिलीज किया था।

2. द राजा साब

रिलीज डेट - 9 जनवरी, 2026

पैन-इंडिया स्टार प्रभास तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म, द राजा साब में नजर आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मारुति दसारी की लिखी और डायरेक्ट की हुई यह फिल्म 9 जनवरी,2026 को स्क्रीन पर आएगी। प्रभास के अलावा, फिल्म में बोमन ईरानी, संजय दत्त,मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल भी लीड रोल में हैं,और ऋद्धि कुमार भी अहम रोल में हैं। फिल्म पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी है।

3. भूत बांग्ला

रिलीज डेट - 2 अप्रैल, 2026

मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बांग्ला में अक्षय कुमार, तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और दूसरे एक्टर अहम रोल में हैं। खास बात यह है कि मशहूर एक्टर असरानी मरणोपरांत फिल्म में दिखाई देंगे। यह 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है।

4. शक्ति शालिनी

रिलीज डेट - 24 दिसंबर, 2026

सैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने मैडॉक फिल्म की शक्ति शालिनी में लीड रोल किया है। खास बात यह है कि शक्ति शालिनी में अनीत पड्डा

के काम करने की घोषणा आयुष्मान खुराना की थम्मा के थिएट्रिकल प्रिंट के साथ रिलीज किए गए एक स्पेशल वीडियो के जरिए की गई थी। इसकी रिलीज डेट की बात करें तो यह बॉलीवुड फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी।

400 करोड़ में बनी फ्लॉप फिल्म

2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने मेकर्स का बड़ा नुकसान कराया था। एक सुपरस्टार और एक स्टारकिड के होने के बाद भी ये फिल्म अपने बजट का आधा भी वसूल नहीं कर पाई थी, जिसके चलते मेकर्स को बड़ा घाटा सहना पड़ा था।

जिसे बनाकर कर्जे में डूबा प्रोड्यूसर, बोला-डायरेक्टर को टाइटल समझ नहीं आया ...

बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में आई हैं,जिन पर मेकर्स ने जी खोलकर पैसे खर्च किए, बदले में इन फिल्मों ने मेकर्स को भरपूर फायदा दिया। लेकिन, 2023 में एक फिल्म ऐसी रिलीज हुई, जो 100 करोड़ी क्लब में एंट्री करने के बाद भी महा-फ्लॉप कहलाई, क्योंकि मेकर्स ने इस पर 400 करोड़ खर्च किए थे। इस फिल्म की रिलीज के बाद प्रोडक्शन हाउस को इतना घाटा हुआ कि निर्माता ने अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन देने के लिए अपना कार्यालय तक बेच दिया और 80 प्रतिशत कर्मचारियों की नौकरी चली गई। हम बात कर रहे हैं 2024 में रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां की, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार नजर आए थे।

400 करोड़ में बनी थी फिल्म

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन स्टार्स वाली ये फिल्म 2024 में ईद के मौके पर रिलीज

हुई थी। इस फिल्म के बजट और स्टारकास्ट के चलते इसका काफी बज भी रहा, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों का इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसके चलते मेकर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा। पूजा एंटरटेनमेंट के तले बनी इस फिल्म पर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने 400 करोड़ खर्च किए थे और फिल्म सिर्फ 100 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई।

डायरेक्टर अली अब्बास जफर पर फूटा असफलता का ठीकरा

बड़े मियां छोटे मियां की असफलता के बाद लंबे समय तक तो वाशु भगनानी ने चुप्पी साधे रखी और फिर फिल्म की असफलता का पूरा ठीकरा डायरेक्टर के सिर पर फोड़ दिया। रौनक कोटेचा के पॉडकास्ट में बात करते हुए वाशु भगनानी ने फिल्म के फ्लॉप होने पर बात की और यहां तक कह दिया कि अली अब्बास जफर के साथ ये फिल्म बनाना, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वाशु भगनानी ने इसी बातचीत में कहा था कि उनके बार-बार समझाने के बाद भी डायरेक्टर अली अब्बास जफर को इस फिल्म का टाइटल ही समझ नहीं आया और उन्होंने इसमें एक्शन डालकर मजा किरकिरा कर दिया।

अली अब्बास जफर को समझ नहीं आया टाइटल

बातचीत में वाशु भगनानी ने कहा था-अली अब्बास जफर को फिल्म का टाइटल ही समझ नहीं आया। हम बोल-बोलकर थक गए कि ये एक कॉमेडी फिल्म है। एक्शन डालो, लेकिन कॉमेडी-एक्शन मत करो। वो इतना ब्यूटीफुल ब्रैंड था, इतना ब्यूटीफुल कि लोग टाइटल से ही अंदर जाना चाहते हैं। बता दें,वाशु भगनानी ने फिल्म की रिलीज से पहले ये तक दावा कर दिया था कि ये 1100 करोड़ तक का कलेक्शन करेगी, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा ही छू पाई।

मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान

इस फिल्म की रिलीज के चलते मेकर्स को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैकी भगनानी के बेटे जैकी ने स्क्रीन से बातचीत में फिल्म की असफलता के बारे में बात की थी। जैकी ने कहा था-यह अनुभव मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख रहा है। हमने इस प्रोजेक्ट में काफी धन निवेश किया, लेकिन मुझे यह समझ आया कि केवल पैसों का पैमाना सफलता की गारंटी नहीं देता। किसी न किसी स्तर पर हमसे गलती हुई – जो कंटेंट हमने बनाया, वह दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंच पाया। दर्शक हमेशा सही होते हैं, और अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया, तो हमें दोबारा शुरुआत करनी होगी और समझना होगा कि कहां चूक हुई। मुझे इसे सीख के रूप में स्वीकार करना होगा और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहरानी होगी। जहां तक रिटर्न की बात है, वह 50त्न से भी कम नहीं है – लेकिन यह हमारे दर्द को कम नहीं कर सकता। एक परिवार के रूप में, हमने इस फिल्म के लिए अपनी संपत्ति तक गिरवी रख दी। अब हमें एहसास है कि कुछ भी कहने या सफाई देने का कोई अर्थ नहीं रह गया है।

प्रियंका चोपड़ा ने जीजू राघव चड्ढा को दी जन्मदिन की बधाई

शेयर की 2 साल पुरानी तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर परिणीति चोपड़ा के पति और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा आज 11 नवंबर अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। नए पापा के लिए परिणीति ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला बर्थडे पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने जीजू के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा। साथ ही बहुत ही प्यारी तस्वीर भी शेयर की, जिसका कैप्शन बड़ा ही मजेदार है।

प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी

मंगलवार,11 नवंबर को प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राघव और परिणीति की सगाई की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह राघव के माथे पर तिलक लगाती दिख रही थीं। तस्वीर के साथ प्रियंका ने लिखा,हैप्पी बर्थडे आपके लिए आने वाला साल सेहत,खुशी और छोटे बच्चे के साथ नए एडवेंचर से भरा हो।

न्यू मॉम परिणीति ने पति राघव पर लुटाया प्यार

परिणीति ने इंस्टाग्राम पर राघव के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर कीं और उनके बर्थडे पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें लिखा था कि जब मुझे लगा कि तुम इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकते... तुम तब और भी परफेक्ट हो गए और दुनिया के सबसे अच्छे डैड बन गए। मैं तुम्हें हमारी जिंदगी के हर पल देखती हूं - एक परफेक्ट बेटे,परफेक्ट पति और परफेक्ट पिता के तौर पर। मैं

तुम्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखती हूं। काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाते हुए। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, मेरा गर्व हो, मेरी ऑक्सीजन हो। सबसे कमाल के इंसान हो। मैं भगवान से लाखवीं बार पूछती हूं... मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या किया? मेरे जीने की वजह को जन्मदिन मुबारक हो। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।

परिणीति और राघव चड्ढा बने पेरेंट्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और क्रिकेटर राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में उदयपुर में एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी की। उन्होंने अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा, लेकिन उस साल की शुरुआत में जब उन्हें कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया तो डेटिंग की अफवाहें उड़ीं। परिणीति और राघव ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में एक ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी में अंगूठियां बदलीं। हालांकि, प्रियंका परिणीति की शादी में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन वह उनकी सगाई की रस्म में बड़ी बहन की ड्यूटी निभाते हुए नजर आई थीं। 20 अक्टूबर को परिणीति और राघव ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। एक्ट्रेस परिणीति ने बेटे को जन्म दिया।

खेल समाचार

जम्मू-कश्मीर ने 65 साल में पहली बार दिल्ली को हराया

रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ एमपी की रोमांचक जीत

आकिब को 5 विकेट

जम्मू-कश्मीर, 11 नवम्बर 2025।

जम्मू-कश्मीर ने रणजी में इतिहास रचते हुए दिल्ली को पहली 7 विकेट से हरा दिया है। 1960 में पहली बार जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी खेला था। तब से अब तक टीम ने दिल्ली को कभी नहीं हराया था।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही दिल्ली की पहली पारी 211 रन पर सिमट गई थी। आकिब नबी ने 5 विकेट लिए। जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 310 रन बनाए। कप्तान पारस डोगरा ने शतक लगाया।

दूसरी इनिंग में दिल्ली ने कप्तान आयुष बडोनी के 72 रन की बदौलत 277 रन बनाए और जम्मू-कश्मीर को 179 रन का टारगेट दिया। टीम से वंशराज शर्मा ने 6 विकेट लिए। मुकाबले के अंतिम दिन मंगलवार को ओपनर कामरान इकबाल ने नाबाद 133 रन बनाए और जम्मू-कश्मीर को जीता दिला दी।

मध्यप्रदेश ने गोवा को हराया

एक अन्य मैच में मध्यप्रदेश ने गोवा को 3 विकेट से हरा दिया। टीम ने 328 रन का टारगेट 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस जीतकर गोवा ने पहले बल्लेबाजी की और 284 रन बनाए। मध्यप्रदेश पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सका। टीम 187 रन पर ऑलआउट हो गई।

गोवा ने दूसरी इनिंग में 230 रन बनाए और एमपी को 328 रन का लक्ष्य दिया। आखिरी दिन हर्ष ग्वाली, शुभम शर्मा और सारांश जैन की फिफ्टी से मध्यप्रदेश ने आखिरी घंटे में टारगेट हासिल कर लिया।

सारांश जैन प्लेयर ऑफ द मैच

मध्यप्रदेश और गोवा के मुकाबले में ऑलराउंडर सारांश जैन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने मैच में कुल 6 विकेट लिए। पहली पारी में 48 और दूसरी पारी में नाबाद 82 रन बनाकर टीम को जीत भी दिलाई।

गोवा की तरफ से सुयश प्रभुदेसाई ने 65 रन बनाए। टीम से दूसरी पारी में अभिनव तेजराणा ने 69 रन बनाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में गोवा से अर्जुन तेंदुलकर ने 3 विकेट लिए।

कामरान इकबाल का शतक,आकिब नबी को 5 विकेट

कामरान इकबाल ने नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली,जबकि आकिब नबी और वंशज शर्मा की गेंदबाजी ने जम्मू-कश्मीर को दिल्ली पर ऐतिहासिक जीत दिलाई।बॉलिंग में जम्मू-कश्मीर से आकिब नबी ने पहली पारी में 35 रन देकर 5 विकेट झटके और दिल्ली को 211 रन पर समेट दिया। दूसरी पारी में जब दिल्ली वापसी करना चाह रही थी, तब वंशज शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 68 रन देकर 6 विकेट लिए और दिल्ली की उम्मीदें खत्म कर दीं।

आयुष बडोनी ने 64 और 72 रन बनाए

दिल्ली की ओर से आयुष बडोनी ने 64 और 72 रन की पारियां खेलीं, जबकि हर्षित दोसेजा ने 65 रन बनाए। लेकिन इन तीनों के अलावा दिल्ली का मध्यक्रम और निचला क्रम लड़खड़ा गया। पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने कप्तान पारस डोगरा के 106 रन और अब्दुल समद के तेजी 85 रन की बदौलत से 310 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने से पहले मोहम्मद सिराज ने भरी हुंकार

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से पहले टीम के आत्मविश्वास पर जोर दिया है। भारत इस सीरीज को नई साइकिल में महत्वपूर्ण मान रहा है।

खुद की गेंदबाजी पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली11 नवम्बर 2025।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से पहले अपनी लय और टीम के आत्मविश्वास को लेकर खुलकर बात की है। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद भारत, शुक्रवार से शुरू होने वाली इस दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज को नई साइकिल में एक महत्वपूर्ण मुकाबला मान रहा है।

मौजूदा चैंपियन के खिलाफ आत्मविश्वास

साउथ अफ्रीका ने भले ही अपने खिताब का बचाव पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के साथ शुरू किया हो, लेकिन भारतीय टीम इंग्लैंड में ड्रॉ सीरीज और वेस्टइंडीज पर घरेलू जीत से उत्साहित है। सिराज ने एक इंटरव्यू में कहा, यह सीरीज नई डब्ल्यूटीसी साइकिल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका मौजूदा चैंपियन है। उन्होंने आगे कहा कि टीम ने एक सकारात्मक माहौल बनाया है और वह अपने अच्छे फॉर्म को लेकर आश्वस्त हैं।

टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले अभ्यास में जुटी

कोलकाता,11 नवम्बर 2025। भारतीय टीम ने मंगलवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले अपना अभ्यास सत्र शुरू कर दिया है। सीरीज़ का पहला मैच शुक्रवार को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को श्रृंखला से पहले अभ्यास सत्र में भाग लेते देखा गया। अभ्यास के दौरान, टेस्ट कप्तान शुभमन गिल मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ खेल योजना पर चर्चा करते नज़र आए। जायसवाल और गिल नेट्स पर थ्रोडाउन के साथ पसीना बहाते नज़र आए, जबकि जायसवाल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और नितीश कुमार रेड्डी कैच अभ्यास सत्र में शामिल हुए।

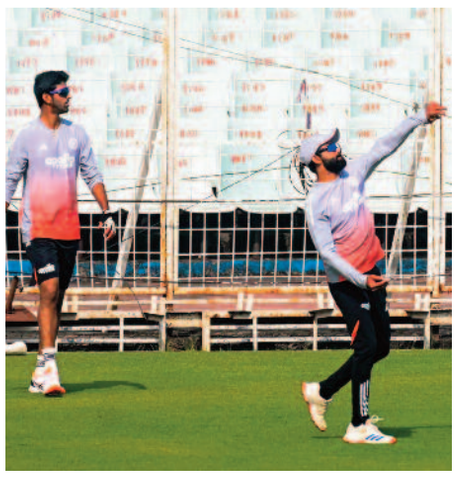

भारत में भारत के खिलाफ खेलना दक्षिण अफ्रीका के लिए कठिन चुनौती होगी

कोलकाता,11 नवम्बर 2025। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ उसकी घरेलू परिस्थितियों में खेलना एक कठिन चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि भारत घरेलू और विदेशी दोनों ही जगहों पर मजबूत है और ईडन गार्डन्स में एक उच्च-स्तरीय मुकाबले की उम्मीद है। भारत शुक्रवार से कोलकाता में शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। गांगुली ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह दौरा कठिन होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटियाज एक अच्छी टीम है और यह एक उच्च गुणवत्ता वाला मुकाबला होना चाहिए। गांगुली ने जियोस्टार पर कहा, पहला टेस्ट कुछ ही दिनों में कोलकाता में शुरू होगा और यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक कठिन दौरा होने वाला है। भारत के खिलाफ भारत में खेलना कभी आसान नहीं होता।

आदिलाबाद ने 58वीं सीनियर तेलंगाना अंतर-जिला खो-खो चैम्पियनशिप में खिताब जीता

पेड्डापल्ली,11 नवम्बर 2025। पुरुषों और महिलाओं के लिए 58वीं सीनियर तेलंगाना अंतर-जिला खो-खो चैंपियनशिप रविवार को यहां पेड्डापल्ली टाउन के इंडिया मिशन हाई स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें रंगारेड्डी पुरुषों के चैंपियन के रूप में उभरे और आदिलाबाद ने चार दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद महिला खिताब जीता। केकेएफआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना खो-खो एसोसिएशन (टीकेकेए), भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) और तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर 6 नक्सलियों का एनकाउंटर

एक जिंदा पकड़ाया,शव और ऑटोमैटिक हथियार बरामद

बीजापुर,11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजपुर जिले में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए सभी नक्सलियों के साथ कई ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जवानों ने बड़े नक्सल लीडर को घेर रखा है। मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई है। जानकारी के मुताबिक, बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ को अंजाम दिया। बीजापुर एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि इंसास, स्टेनगन, 303 राइफल, विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। वहीं बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि सुरक्षाबलों के लिए एक निर्णायक और महत्वपूर्ण बढ़त है। यह सफलता ऐसे समय में मिली है, जब माओवादी संगठन नेतृत्वविहीन, दिशाहीन और मनोबलहीन स्थिति में अपने कुछ बचे हुए ठिकानों में सिमटकर रह गया है।

वहीं छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर तारलागुड़ क्षेत्र में अन्नाराम के जंगलों में भी पुलिस-नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के दौरान एनकाउंटर स्पॉट से एक घायल नक्सली को पकड़ा है। नक्सली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इलाज भी चल रहा है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, नक्सली सरेंडर करेंगे, उन्हें वापस आने का सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा। आने के बाद पुनर्वास भी कराया जाएगा। वर्ना जो प्रक्रिया है सर्चिंग की वो चलेगी। अगर नक्सलियों की तरफ से हमला होता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इन सबके बीच नक्सल कमांडर हिड़मा की मां माड़वी पुंजी और नक्सल लीडर बारसे देवा की मां बारसे सिंगे ने गृहमंत्री विजय शर्मा के सामने अपने-अपने बेटों से सरेंडर करने की अपील की है। दोनों की मां ने कहा कि घर लौट आओ बेटा। गांव में ही कमाई करेंगे और खाएंगे।

हिड़मा की मां ने कहा...

हिड़मा की मां माड़वी पुंजी ने अपने बेटे से कहा कि कहां पर हो, आ जाओ कह रही हूं। नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं, कहीं आसपास रहता तो जंगल में ढूढ़ने भी जाती, और क्या कहूं बेटा, घर आजा बोल रही हूं। घर आजा। गांव में ही कमाई करके खाएंगे,जीएंगे। जनता के साथ जी लेना आ जाओ।

अब कहां है हिड़मा

अब तक नक्सलियों की बटालियन नंबर-1 को लीड कर रहा खूंखार नक्सली हिड़मा को माओवादियों की सबसे बड़ी कमेटी सीओसी यानि सेंट्रल ऑर्गनाइजिंग कमेटी में जोड़ा गया है। ये वह कमेटी होती है, जिसमें देशभर के माओवादी विचारधारा के मजबूत व्यक्तियों को लिया जाता है।

नक्सली बारसे देवा की मां ने क्या कहा ?

वहीं नक्सली बारसे देवा की मां बारसे सिंगे ने कहा कि बेटा घर आजा। यहां घर पर ही रहकर कमाई करके जीएंगे। मत जाओ बोली थी, लेकिन चला गया। घर में ही नांगर-कुली करने वाले कोई नही हैं। घर आकर सरेंडर कर दे। घर में कमाई करके खाएंगे। घर आने से अच्छा रहेगा।

छत्तीसगढ़ और गुजरात मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका : सीएम साय

रायपुर,11 नवम्बर 2025। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,321 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्युटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र प्रदान किए।छत्तीसगढ़ को मिले इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में 14,900 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यवसायिक नेतृत्व से राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। उद्योगपतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, निवेश और नवाचार की भूमि गुजरात में आकर वे अत्यंत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के कण-कण में उद्यमिता बसी है और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, जहां गुजराती भाइयों की उपस्थिति न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। साय ने कहा कि गुजरात जिस प्रकार देश और विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास उद्यम है, तो छत्तीसगढ़ के पास ऊर्जा, खनिज, कुशल जनशक्ति और आकर्षक औद्योगिक नीति है–जो निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 22 महीनों में 350 से अधिक सुधार किए हैं, जिनसे उद्योग स्थापित करना और अधिक सुगम हुआ है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक अनुमतियाँ अब त्वरित रूप से जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को विशेष अनुदान एवं प्रोत्साहन दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय अंचलों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और हाल ही में आयोजित एनजीं समिट में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य में थर्मल, हाइडल, सोलर और वन-आधारित उद्योगों की विशाल संभावनाएँ मौजूद हैं।

पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर हाईकोर्ट ने लगाया 1000 का जुर्माना

प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर नहीं दिया एफिडेविड,डिवीजन बेंच ने जताई कड़ी नाराजगी

बिलासपुर,11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के अफसर हाईकोर्ट के आदेशों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस तरह से प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही और टालमटोल रवैए पर सख्त रुख अपनाना जरूरी है। दरअसल, डिवीजन बेंच ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से शपथपत्र मांगा था। जवाब देने में देरी की वजह से कोर्ट ने जुर्माने की कार्रवाई की है। दरअसल, हाईकोर्ट में राज्य की बदहाल सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने बिलासपुर के पेंड्रीडीह बायपास से नेहरू चौक तक की सड़क को लेकर भी सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने मरम्मत और नई सड़क निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही कहा था कि एनआईटी रायपुर की रिपोर्ट जल्द ली जाए, ताकि नई सड़क का काम तेजी से शुरू किया जा सके।

नक्सलियों ने कहा...नहीं डालेंगे हथियार,ऑपरेशन पर निकली फोर्स

जगदलपुर,11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को देखते हुए नक्सलियों ने एक बार फिर पत्र जारी किया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि, उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे किसी भी स्थिति में हथियार नहीं डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सोनू और सतीश को दोबारा गद्दार और पार्टी विरोधी करार दिया है। नक्सलियों ने लिखा कि, दोनों ने अपने पद और जिम्मेदारी का दुरुपयोग किया तथा निचले कैडर को भटकाने का प्रयास किया। इन दोनों ने केंद्रीय कमेटी की नीतियों को कमजोर करने और संगठन को बदनाम करने की साजिश रची है। पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि, कुछ पूर्व सदस्य अब सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं और संगठन की अंदरूनी जानकारी बाहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि, बस्तर में नक्सलियों के कई बड़े कमांडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्य सरकार और पुलिस ने नक्सल उन्मूलन के लिए विकास और संवाद की नई पहलें शुरू की हैं। इसी बीच यह पत्र जारी होना नक्सल संगठन की बढ़ती बेचैनी और आंतरिक असंतोष का संकेत माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पत्र की प्रामाणिकता और स्रोत की जांच में जुटी हैं। सूत्रों का कहना है कि यह पत्र बस्तर के दक्षिणी क्षेत्र से जारी किया गया है।

पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत

सरपुर निगम नेता-प्रतिपक्ष आकाश तिवारी पीड़ित परिवार से मिले

रायपुर,11 नवम्बर 2025। रायपुर में कबीर नगर थाना क्षेत्र के हीरापुर में सरकारी स्कूल के पास खेल रहे दो बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए और डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान सत्यम (8 साल) और आलोक (7 साल) के रूप में हुई है। दोनों मौसेरे भाई थे और अपनी मौसी के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने रायपुर आए थे। हादसे के बाद नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी तिवारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद घटना स्थल का मुआयना भी किया। तिवारी ने मामले कहा कि यह नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि इसी गड्ढे में पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन न तो निगम ने और न ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम उठाया। तिवारी ने बताया कि, बिल्डर की ओर से पीड़ित परिवार को 15-15 लाख मुआवजा देने की बात हुई है।

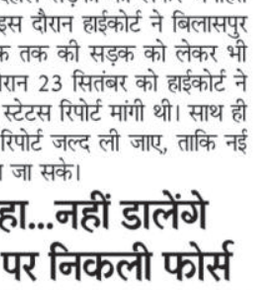

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल पर इनाम घोषित एसएसपी ने सूचना देने पर 5000 के नगद पुरस्कार का किया ऐलान

रायपुर,11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में अपराधिक प्रकरण दर्ज है। अमित बघेल ने सिंधी समाज को लेकर अपशब्द कहे थे,जिसके बाद उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों में बढ़ते रोष को देखते हुये रायपुर पुलिस ने अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू की। रविवार 9 नवंबर की रात रायपुर के कई इलाकों में पुलिस ने दबिश दी और उनके परिचितों से पूछताछ भी की, मगर वे नहीं मिले।

इसी बीच रायपुर पुलिस ने अमित बघेल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने अमित बघेल का पता बताने और गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 5000 का पुरस्कार घोषित किया है। पुलिस ने उद्घोषणा जारी कर कहा है कि जो भी पुलिस की मदद करेगा, उसे 5000 नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर के अपराध कमांक अपराध क. 243/2025 धारा 299 भा. न्याय संहिता के प्रकरण में फरार आरोपी अमित बघेल पिता रामकुमार बघेल साकिन रामसरस कंचन गंगा स्टेट फेस 02 सरस्वती शिशु मंदिर के पास रोहनीपुरम जिला रायपुर का निवासी है। जो दिनांक 28/10/2025 को उपरोक्त अपराध घटित कर फरार है अपराध कायमी पश्चात् आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये गये हैं जो अभी तक पता नहीं चला है। प्रकरण में फरार आरोपी स्वयं को पुलिस से बचाने के लिये अपने आपको छिपाए हुए है। फरार आरोपी द्वारा भविष्य में भी गंभीर किस्म का अपराध कारित किया जा सकता है। ऐसे आरोपी का स्वच्छंद विचरण करना समाज के लिए घातक है। अतः मैं डॉ. लाल उमेद सिंह (भा.पु.से.) उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करता हूं, कि जो कोई उक्त फरार आरोपीं को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करवायेगा, अथवा युक्ति-युक्तकरण सूचना देगा जिससे फरार आरोपी को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सके, उसे 5,000/- रूपये (पाँच हजार रूपये/-) के नगद राशि से पुरस्कृत किया जावेगा।

अमित बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने अमित बघेल का समर्थन किया है। समिति अध्यक्ष रूपनलाल चंद्राकर, सचिव कामता प्रसाद रात्रे, प्रवक्ता गिरधर पटेल ने समर्थन पत्र में कहा कि अमित बघेल को गिरफ्तार करना तो दूर एक खरोंच भी आई तो समिति उग्र आंदोलन करेगी। समर्थन पत्र में नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने लिखा है...महान सपुत छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टया श्रध्देय खूबचंद बघेल जी के सुयोग्य नाती अमित बघेल जी अध्यक्ष जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी 8 छत्तीसगढ़ियों को शासन-प्रशासन, उद्योग-व्यापार में भागीदारी. हक-अधिकार दिलाने, सदैव संघर्षरत हैं, इसी तारतम्य में उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा को खंडित किया जाता हैं, अपमानित किया जाता है, छत्तीसगढ़ियों को हर जगह अप- मानित, दीन-हीन समझा जाता है। सिंधी समाज के पुज्य महापुरषों, अग्रवाल समाज के पुजनीय अग्रसेन महराज के प्रतिमाओं को खंडित क्यों नहीं किया जाता? बार-बार छत्तीसगढ़ियों के मान-सम्मन, संत-महापुरषों, देवी-देवताओं का बाहरियों द्वारा अपमान किया जाना जारी हैं...यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का शोषण व अपमान करना जारी है, नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति, इसकी हम घोर निन्दा करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ स्वाभिमानी कथन के कारण अन्य गैर छत्तीसगढ़ियों के दबाव में हमारे मूल छत्तीसगढ़िया, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला क्रांतिवीर अमित बघेल जी पर एफ. आई. आर. दर्ज की गई है...और जगह-जगह एफ.आई.आर. दर्ज करने का षड़यत्र जारी हैं। नई राजधानी प्रभाविज किसान कल्याण समिति नया रायपुर, सर्वप्रथम अअमित बघेल जी हुए कुत्सित एफ. आई. आर. को रद्द करवाने छ.ग. शासन-प्रशासन से अपील करती हैं।

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज

रायपुर,11 नवम्बर 2025। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। खाद्य विभाग में पदस्थ रहे रिटायर्ड असिस्टेंट फूड ऑफिसर संजय दुबे के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक,पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि संजय दुबे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मामले को उजागर करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार,संजय दुबे राजधानी के चर्चित खाद्य अधिकारी रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कई बार विवादों में घिरे रहे हैं। वे पूर्व में भी दो अलग-अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। पहला मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा था, जब उन्हें खाद्य विभाग में पदस्थ रहते रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उस समय उनका मामला काफी चर्चित रहा था। दूसरी बार वे महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण सुर्खियों में आए थे। सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक भावना आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। अब एक बार फिर संजय दुबे गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस जल्द ही कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। आरंग थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि 'आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए जांच प्राथमिकता से की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर ली गई है। ' स्थानीय सूत्रों का कहना है कि संजय दुबे से जुड़े विवाद पहले भी विभागीय स्तर पर उठ चुके हैं। हालांकि, हर बार वे किसी न किसी तरह से बच निकलने में सफल रहे। लेकिन इस बार मामला बलात्कार और धमकी से जुड़ा होने के कारण पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। राजधानी में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि संजय दुबे का नाम पहले से ही कई संवेदनशील मामलों में सामने आ चुका है। अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं और आरोपी कब तक गिरफ्त में आता है।

SECR के डिप्टी CCM पर गंभीर आरोप

महिला कर्मचारी से अश्लील चैट और यौन उत्पीड़न,जांच में दो महीने की देरी पर उठे सवाल..

बिलासपुर,11 नवम्बर 2025। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला कर्मचारी ने डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर कौशिक मित्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चांपा में कमर्शियल क्लर्क के पद पर पदस्थ पीड़िता ने रेलवे के महाप्रबंधक को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें अधिकारी द्वारा किए गए उत्पीड़न के 12 बिंदुओं का उल्लेख है।

व्हाट्सऐप चैट के जरिए लगातार उत्पीड़न : पीड़ित महिला कर्मचारी का आरोप है कि अधिकारी कौशिक मित्रा व्हाट्सऐप चैट के जरिए उसे लगातार परेशान कर रहे थे और उससे अनुचित मांगें कर रहे थे। अधिकारी लगातार महिला कर्मचारी से जिम से सेल्फी भेजने के लिए कहते थे। चैट में अधिकारी ने महिला से असुविधाजनक सवाल पूछे, जैसे कहां कंफर्टेबल होकर मिल सकते हैं? और क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? पीड़िता का कहना है कि अधिकारी उसे हर दिन परेशान करते थे, जिससे उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया था। महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि इस संवेदनशील मामले को दर्ज हुए दो महीने बीत चुके हैं।

1.50 लाख की रिश्वत मांग रहा था नायब तहसीलदार,एसीबी ने 50 हजार लेते रंगे हाथ दबोचा..

बिलासपुर, 11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सीपत तहसील के नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार ने एक किसान से उसकी मां की मौत के बाद फौती (उत्तराधिकार) रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की मांग की थी। सोमवार को एसीबी ने उन्हें पहली किश्त की राशि लेते पकड़ा है।

फौती दर्ज करने मांगी थी बड़ी रकम : एसीबी के डीएसपी ने बताया कि 30 अक्टूबर को सीपत तहसील के ग्राम बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटनवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। किसान ने बताया कि उसकी माता का देहांत हो चुका है और उनके नाम पर गांव में करीब 21 एकड़ कृषि जमीन दर्ज है। इस जमीन के रिकॉर्ड में फौती दर्ज कर किसान और उसके भाई बहनों का नाम दर्ज कराने के लिए वह नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे से मिला था। नायब तहसीलदार कुर्रे ने इस काम के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की डिमांड की थी।

किसान ने बनाई रंगे हाथ पकड़वाने की योजना : नायब तहसीलदार द्वारा पैसे की डिमांड करने पर किसान प्रवीण पाटनवार ने उसे सबक सिखाने और रंगे हाथों पकड़वाने की योजना बनाई। किसान ने सौदा तय करने के बाद पैसा देने के बजाय मामले की शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया, जो सही पाया गया। सत्यापन के दौरान किसान ने नायब तहसीलदार से दोबारा बातचीत की, जिसके बाद अधिकारी 1 लाख 20 हजार रुपये में काम करने के लिए सहमत हो गया।

कॉफी हाउस में पकड़ा गया घूसखोर अधिकारी : एसीबी ने अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की पूरी प्लानिंग की। सोमवार को किसान ने पहली किश्त की राशि 50 हजार रुपये देने के लिए नायब तहसीलदार कुर्रे से संपर्क किया।दोपहर में नायब तहसीलदार ने किसान को एनटीपीसी के कॉफी हाउस में बुलाया। इस दौरान एसीबी की टीम भी पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गई। जैसे ही किसान ने नायब तहसीलदार कुर्रे को 50 हजार रुपये थमाएएसीबीकी टीम ने उन्हें तुरंत दबोच लिया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)